पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

साप्ताहिक

# समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Website: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9300755803, 9425125569
Phone Fax: +91 731 2530859

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 7 अंक 42 प्रति सोमवार इंदौर, 12 से 18 अगस्त 2013 पृष्ठ 8 मूल्य 2/- रुपए

### पाक की तरह चीन के साथ मिलकर कांग्रेसी सत्ताधीश रच रहे षड़यंत्र

## उत्तराखंड की भीषण तबाही में सत्ताधीश, चीन के साथ

**परिस्थितियां सामान्य होने के साथ ही उत्तराखंड में चीनी घुसपैठ चारों तरफ चीनी माल से भारतीय बाजार भरे पड़े...**

**देशी उत्पादकों को स्वयं सरकार ने बर्बाद किया। सत्ताधीश चीन से कमीशन डकार, घुसपैठ पर आंखे मूंदे जम्मू कश्मीर की तरह पूरा उत्तराखंड, हिमाचल, हिन्दुओं से खाली कराने का षड़यंत्र...**

**विधि मंत्री सलमान खुर्शीद की चीन यात्रा के बाद उ.मु.मं. की ठीक पूर्व विदेश यात्रा की तैयारी**

कांग्रेस अंग्रेजों की यह अवैध औलाद जिसे अंग्रेजो ने 1885 में पैदा किया था। आजादी के बाद का देशी संस्करण, उन आकाताओं से ज्यादा घूर्त मक्कार, दोगले आकांता है। जिन्हें राष्ट्र से नहीं अपनी लूट-खसौट, वसूली से मतलब है। इनका इतिहास रहा है कि ये किसी भी हद तक गिर कर, स्वाभिमान त्याग कर, अपनी भोग लिप्सा, स्वार्थ सिद्धी में व्यस्त रहते है। पाकिस्तान के आतंकियों के साथ मिलकर, राष्ट्र में कश्मीर से कन्या कुमारी, मुंबई से आसाम, नागालैंड तक अनेकों विस्फोटों मे पिछले 40 वर्षों में लाखों को मार चुक हैं। इन कांग्रेसी जालसाजों ने जैसे जम्मू-कश्मीर में मुस्लिम आतंकियों को आमंत्रित कर हिन्दुओं से खाली करवा डाला, वैसे ही उत्तरांचल के बाद की भीषण तबाही का षड्यंत्र रचकर, पूरा उत्तरांचल, हिमालय, हिंदू विहीन करना चाहते हैं। असम से लेकर मेघालय, नागालैंड तक बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाने का बड़ा सिलसिला पिछले 40 वर्षों से निर्बाध जारी है। देश में हिंदुओं की नसबंदी कर हिन्दुओं की आबादी घटाई जा रही है, दूसरी और कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक को बढ़ाने 5 बीबीयों से 50 बच्चे पैदा कर देश पर जनसंख्या का बोझ लाद हिन्दुओं द्वारा चुकाये करों से उनकी परवरिश कर आजादी के बाद से 25 प्रतिशत आबादी को 60 प्रतिशत करने में आंखभींच कर जुटी है, ताकि पूरे देश की विधान सभाओं और लोकसभा पर उसका एकाधिकार बना रहें।16 जून 13 को 11 बजे उत्तरांचल में आई भीषण बाढ़ कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, वरन चीन के साथ कांग्रेस का पूर्व नियोजित



षड़यंत्र था। इसीलिये उत्तरांचल के कांग्रेसी मु.मं. विजय बाहुगुणाने छुट्टियां मनाने स्विटजरलैंड भागने की तैयारी थी, पर ठीक समय से 6 घंटे पूर्व 11.00 बजे से ही तबाही शुरू हो जाने के कारण प्रधानमंत्री कार्यालय ने जाने से रोक दिया। 15 जून की रात 3-4 बजे से चीन ने ऊपर का रसायनों से तापमान बढ़ाकर बर्फ पिघलाना शुरू कर जो सुबह 6-7 के बीच केदारनाथ के 2 ग्लेशिर्यस पिघलकर तेजी से भारी हिमखंडों के साथ नीचे की तरफ आने से सरोवर को फोड़ते हुए निकले, कंपेनियन के साथ चुरावरी हिमनंद गांधी सागर बांध को तोड़ते हुए बह निकले।

**(शेष पेज 3 पर)**

### आतंक, क्रिकेट के सट्टे की आड़ में जारी है कांग्रेस के षड्यंत्र

## बढ़ता डालर... काले धन वालों को भारत में लाने पर फायदा

**रिजर्व बैंक व अन्य सरकारी बैंकों को अपने बाप की जागीर समझ अपने लाभ के लिये कर रहे उपयोग**

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मुद्रा का जिस तेजी से अवमूल्यन बना और अपने हितों के साधने के लिए वित्तमंत्री द्वारा करवाया जा रहा हैं, जिसमें भारतीय बैंकों द्वारा जानबूझकर अमेरिकी डालर की खरीदी करवाकर मुद्रा बाजार में कमी पैदा कर डालर की कीमत बढ़वाई गई, दूसरी तरफ निर्यात में कमी आने और पेट्रो क्रूड की नियमित व अन्य आवश्यक सामानों की खरीदी पर भुगतान के संकट ने भी रुपये के अवमूल्यन में आग में घी का कार्य किया, जहां तक आयात निर्यात से रुपये की कीमत गिरने का संबंध है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसके विपरीत जब बाजार की स्थितियां प्रतिकूल हों, जानबूझकर भारतीय बैंकों द्वारा डालर की खरीदी करना पूर्णतः षड्यंत्रों की कहानी स्वमेव कहता है। आखिर रुपये की कीमत जब कालेधन को राष्ट्र में लाने के विवादों के बाद ही क्यों गिरती हैं, क्योंकि कालाधन अधिकांश राजनेताओं उच्चाधिकारियों जिसमें मुख्यतः इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारियों और राष्ट्र के गिने-चुने पूंजीपतियों जो संख्या में हजार से ज्यादा भी नहीं है का ही है, इतने हो-हल्ले के बाद उन्होंने उस धन को विदेशी बैंकों से निकालकर भारत लाना शुरू कर दिया हैं, इस तथ्य की पुष्टि स्विट्जरलैंड की बैंकों से भारतीय धन निकाला जा रहा हैं, स्वाभाविक है लाये जाने वाला धन जो रु. 30-40-50 के भाव में जमा किया गया था, उसके अब सीधे रु. 60 प्रति डालर मिल रहा है। जिससे बैठे ठाले मोटी अरबों रु. में कमाई भी इन राजनेताओं, अधिकारियों और पूंजीपतियों को ही हो रही हैं, जिसमें हिस्सा हमारे वित्तमंत्री पी. चीटअंबर और कांग्रेस को भी अप्रत्यक्ष रूप से मिल ही रहा है। बेशक इससे डालर की आपूर्ति बढ़ने से डालर की कीमतें कम होनी चाहिये थी, जिसके लिये भारतीय बैंकों ने उसकी भरपाई करने के लिए तबाड़तोड़ खरीदी कर डालर की कमी पैदा कर दी।

भुगतान संकट को हल करना बहुत बड़ी बात नहीं थी, परन्तु जब षड्यंत्रों को अंजाम देकर लाभ कमाने की मानसिकता ही बना ली तो फिर रुपये के अवमूल्यन को रोकने की औकात अकेले बाजार की परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं की जा सकती। भारत का वित्त मंत्री इतिहास, वर्तमान और भविष्य का सबसे बड़ा जालसाज, भ्रष्ट और चालबाज चीटाअंबर अपने लाभ के लिये सब कुछ किया है, कर रहा है, और करता रहेगा, जिसके इतिहास में प्लांटेशन कं., चिटफंड कं. का युलिप का यूनिट ट्रस्ट घोटाला, हर्षद मेहता कांड आदि के लाखों करोड़ जनता के हजम करने में भी इसकी महती भूमिका रही है।

जनता का और मीडिया का ध्यान बंटाने के लिए कभी क्रिकेट, बाढ़ आतंक में उलझाये रखकर अपने षडयंत्रों को अंजाम देते रहते हैं। स्वाभाविक है इसके परिणामस्वरूप जनता महंगाई की मार झेलने के लिये मजबूर हो जाती है। क्योंकि रु. के अवमूल्यन का सीधा असर पेट्रोल-डीजल की कीमतों के बढ़ने से सभी खाद्य और अखाद्य वस्तुओं की ढुलाई लागत पर आयेगा और महंगाई बढ़ेगी पर जहां तक कांग्रेस का सवाल है, **(शेष पेज 4-5 पर)**

### जापानी फौजी प्रशिक्षण दिया जाए सेना को

## हर क्षेत्र में जापानी सहयोग लेकर दो चीन को सबक

**जापान का नाम सुनते ही भकड़ने लगता है चीन, इलेक्ट्रानिक्स, औद्योगिक फौजी तकनीक का उपयोग कर हर क्षेत्र में मात दो चीन को**

विश्व भर में अपनी राष्ट्रभक्ति, लड़ाकू, कर्मठ और सूक्ष्म प्रकाशीय, यांत्रिकीय इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रानिक्स, वस्त्र व अन्य अनेकों क्षेत्रों में जापानियों की कोई होड़ नहीं है, जापानियों और जापान सरकार का



बौद्ध धर्म की उद्गम स्थली और अध्यात्म के केन्द्र के रूप में भारत से स्नेहिल श्रद्धा का नाता रहा है और वे भारत के ऐतिहासिक रूप से सदा सहयोगी रहे हैं। जापान ने अनेकों भारतीय कं. से आटो मोबाइल क्षेत्र में सहयोग करके भारत को कारें व बाइक्स के निर्यातक के रूप में विश्व में प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, परंतु भारत के धूर्त सत्ताधीश कांग्रेसियों और आई.ए.एस.अधि. को मोटा कमीशन और रिश्वत के अभाव में इन हरामखोरों का जापान के प्रति उदासीन रवैया रहा, यदि ये मुखेरे जापान को तरीके से सहयोग करें तो जापानी कं. और प्रशासन न केवल औद्योगिक, सामरिक विकास में सहयोग करने के लिये तैयार हैं। **(शेष पेज 3 पर)**

### विश्व व एशियन विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का षड्यंत्र

## लाखों करोड़ों डकारने के लिये, हजारों करोड़ों का ऋण

**बिजली, पानी, सड़कें राष्ट्रीय संपत्तियों पर राज्यों में बनवाए निगम, जो घाटे में बताकर संपत्तियां सौंप रहे निजी क्षेत्र में**

संयुक्त राष्ट्र संघ यथार्थ में युरोपियन राष्ट्रों का संयुक्त शैतान संघ है। जो अमेरिकी राष्ट्रीय बैंको षड्यंत्रों की उपज है, जिसका दिवा स्वप्न है कि विश्व के राष्ट्रों की प्राकृतिक और मानव संपदा पर कब्जा कर उन्हें अपने स्वार्थों की आपूर्ति का साधन बनाना या उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से गुलाम बनाकर अपनी स्वार्थ सिद्धी करना।

भारत के मारवाडी-बनिये जिनकी मूर्ति जयपुर के राजकीय संग्रहालय प्रवेश द्वार के बांयी तरफ ही जोड़े के साथ रखकर नीचे विवरण दिया गया है कि कैसे मारवाड़ी जोड़ा किसी गांव में घुसकर पहले छोटा-मोटा व्यवसाय करता हैं, लोगों में घुल-मिल जाता है, फिर उनकी आवश्यकतानुसार उन्हें उधार सामान और उनकी संपत्तियों को रहत रखकर ऋण बांटता है और ऋण पर ब्याज की ऊंची दरों में ही ऋण स्थिर रखकर उस गांव के



लोगों की जमीने हड़प कर गांव के लोगों को ही बंधुआ मजदूर बना लेता हैं, इसलिये ऐसे सूदखोरों से बचने की सलाह दी गई है। बिलकुल इसी तर्ज पर ईस्ट इंडिया कं. ने भारत पर कब्जा किया था, इसी तर्ज पर संयुक्त शैतान संघ के ये अनुषांगिक संगठन, विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक और अंतराष्ट्रीय मौलिक संगठन कार्य कर रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य भी यही था जिसका विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में 1990 से भारी विरोध किया गया था, जिसके लागू करने और करवाने में विश्व के बड़े पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कं. का भी यही उद्देश्य था कि पहले विकास के नाम पर ऋण बांटो फिर उसके डूब जाने का इंतजार करों वहां बैठे मंत्रियो, अधिकारियों, इंजिनियरों को धन हड़पने और भ्रष्टाचार में डुबाओं और बाद में वसूली के नाम पर अपनी शर्तें थोपो, फिर उन सेवाओं तथा बिजली, पानी, सड़कों, संचार आदि को निगमों, कंपनियों में बदलो व्यवसायिक स्वरूप दो, फिर उन कं. निगमों उसकी एबीसीडी भी न आती हो, उन्हें केवल लूटना और वसूली करना आता है। जैसा कि देश के विद्युत मंडलों को तोड़कर पहले कंपनी में बांटा गया फिर उन कं. के छोटे-छोटे टुकड़े किये गये। अपने मप्र में विद्युत क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र आदि कं. में बांटा गया, इसमें उन घूर्त इंडियन एव्यूसिंग सर्विस को चुन-चुन कर उन भ्रष्ट अधिकारियों को बैठाया गया जो इंजिनियर तो थे ही नही, **(शेष पेज 7 पर)**

साप्ताहिक समय माया

# संपादकीय

## शीर्ष सत्ताधीश भ्रष्टऔर अपराधी

भारत राष्ट्र की धरती का यह दुर्भाग्य रहा है कि यहां पर अनादिकाल से लेकर धूर्त, स्वार्थियों का ही हर काल में बोलबाला रहा हैं, यदि ,क ओर श्रेष्ठ देवों, ज्ञानी, ध्यानी, ऋषि, मुनि, ब्रह्मज्ञानियों का जन्म हुआ है, तो दूसरी ओर महाराक्षसी प्रवृत्ति के दानवों का जन्म हुआ हैं, जिसका प्रभाव वर्तमान में भी देखा जा सकता है। यदि एक ओर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शीर्ष सत्ता को भ्रष्टों और अपराधियों से मुक्त रखना चाहता हैं, तो दूसरी ओर हमारे शीर्ष सत्ता में बैठे जनता के चुने सांसद, विधायकों को ये हजम ही नहीं हो रहा, उल्टे ही एक श्रेष्ठ संस्था के न्यायाधीशों को, जिन्हें उन्होंने ही मनोनीत करवाया, ताकि राष्ट्र की कानून व्यवस्था में न केवल राष्ट्र की जनता का विश्वास बना रहे वरन् राष्ट्र की सत्ता राष्ट्र में लागू कानूनों के अंतर्गत सुचारु रूप से चलाई जा सकें, इस वर्तमान में विश्व भर में सभी राष्ट्रों की सत्तायें इसी आधार पर सुचारु रुप से चलाई जा सक रही हैं कि वहां पर समाज और राष्ट्र को चलाने के लिए समान नागरिक आचार संहिताओं, नियमों और कानूनों का पालन कठोरता से किया जा रहा हैं, परन्तु विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस लोकतांत्रिक राष्ट्र में शीर्ष सत्ता से लेकर राष्ट्र की संसद, राज्यों की विधानसभाओं, क्षेत्रीय नगरीय क्रियों आदि से लेकर ग्राम पंचायतों तक बैठे हुए चुने हुए जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक सेवा में बैठे अधिकारी तक अनेकों अपराधों के न केवल आरोपी वरन् सजायाफ्ता तक कुंडली मारे बैठे सत्ता चला रहे हैं, जनहितों के मुद्दों पर वर्तमान और भविष्य के लिये धन आवंटन नीति र्धारण कर रहे हैं। स्वाभाविक है जिनकी पृष्ठभूमि अपराधों से भरी हुई हैं, जो केवल आपराधिकता के कारण भय और दहशत से जनमत प्राप्त कर सत्ता तक पहुंचे हैं, वे अपने चरित्रिक आपराधिक मानसिकता के चलते क्या जनता के बीच किस आदर्श के साथ अपने आप को वर्तमान और भविष्य के किस कल्याणकारी कृत्यों के साथ प्रस्तुत करेंगे या पूरे विश्व के मीडिया में इस की छवि से राष्ट्र और राष्ट्र की जनता की क्या छबि बन रही है, ये आपराधिक नेता भलीभांति जानते हैं। इन्हें अपनी आपराधिकता से, समाचार माध्यमों में इनके आपराधिक विश्लेषण और प्रस्तुति से तनिक भी आत्मग्लानि तो होती ही नहीं वरन जनता के बीच सत्ता गुरूर में उल्टे ही जनता को आदर्श सिखाने, बताने और अपनी महानता सिद्ध करने के साथ फिर से वोट मांगने पहुंच जाते हैं। एक तरफ याचना करते हैं तो दूसरी तरफ खुले में धमकाते हैं। इन्हें आत्मग्लानि हो न हो पर मतदाता को अवश्य होती हैं, इसीलिये शिक्षित मतदाता या तो वोट देने ही नहीं जाता या फिर सबसे कम अपराधी नेता को मजबूरी में वोट देकर आता हैं, राष्ट्र के 125 करोड़ मतदाता में 50 करोड़ मतदाताओं को तो लालच में, 10 करोड़ मतदाता दहशत में वोट डालने जाते हैं। 60 करोड़ मतदाता जो शिक्षित हैं। 25% ही अपने आकाओं को अपने स्वार्थों के चलते ही वोट देते हैं। बाकी मतदाता मतदाताओं की लाइन में खड़े होना अपनी शान कम होने, सत्ता में बैठे भष्टाचारी नेताओं, चुनाव में खड़े उम्मीदवारों की आपराधिकता, भ्रष्टाचार के कारण भी वोट देने नहीं जाते। राष्ट्र की एकमात्र संस्था ने ये पहल करके, कम से कम जनता को न केवल राष्ट्र की वरन विश्व की ये तो बता ही दिया कि आत्मा से वे भी नहीं चाहते की सजायाफ्ता और आपराधिक व्यक्ति राष्ट्र की सत्ता में भागीदारी करें, परन्तु राजनैतिक पार्टियों के दिग्गज धूर्त ये जानते हैं कि ये ही आपराधिक वृत्ति के नेता ही साम, दाम, दंड, भेद के दम पर ही सत्ता हथिया कर राष्ट्र की जनता को हांककर राष्ट्र की संपत्तियों का दोहन कर संपत्ति इकट्ठी कर सकते हैं। न तो शिक्षित सीधा-सादा चरित्रवान व्यक्ति नेता बन नेता गिरी कर सकता हैं, न ही येन-केन-प्रकरेण चुनाव जीत सकता है, इसीलिये ही आपराधिक व्यक्तियों को सत्ता में लाने के लिये सारी पार्टियों के एक-दूसरे के घुर विरोधी नेता भी एकजुट हो संसद में प्रस्ताव पारित करने पर एकजुट हो गयें, अर्थात इतिहास की पुनर्रावृत्ति ही होगी कि नीच आपराधिक पाश्विक प्रवृत्ति के दानव ही इस राष्ट्र के घोर स्वार्थी मानव पर शीर्ष सत्ता में बैठकर हांक सकते हैं। पृथ्वी पर जन्मे मानव अपने सदकर्मों से देव और उत्पत्ति प्रकृति से ही दानव सिद्ध होते हैं।

### जब भू-राजस्व की जिम्मेदारी जिलाधीश की, भू-अर्जन का कार्य उप सहा. जिलाधीश का

# क्यों फंसाया जाता है? कार्य विभागों के कार्य.यंत्रियों को न्यायिक प्रकरणों में

**जबकि हर का. विभाग से 10% खर्च, भूमि की कीमत के अतिरिक्त जिलाधीशों को दिया जाता है**

भारत में अंग्रेजों के समय कलेक्टर का काम अंग्रेजों के लिये जिले का भू राजस्व संग्रहित करना था। कमिशनर का काम संभाग के जिलों में जिलाधीश द्वारा संग्रहित राजस्व को अपने राजस्व में से कमीशन काट अपने आकाओं को भेजना था। आजादी मिलते ही इन पेन्सिलखे कलेक्टरों, कमिश्नरों ने देखा कि जो भी नेता, मंत्री, प्रधानमत्री सब मूर्ख है, इन्हें न तो ढंग से कानून का ज्ञान है, न प्रबंधन का, बस इनकी उचटके लग गई है। ये सारे हरामखोर, जालसाजों ने नगरीय सेवाओं को प्रशासनिक सेवा में बदलने का षड़यंत्र रचकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीयों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों के कार्यालयों से, सभी मंत्रालयों में सचिवों, प्र.स. आयुक्तों, जिलाधीशों यहां तक कि तहसीलों में भी न्यायिक भू राजस्व आदि उपजिलाधीशों, दंडाधिकारी तक पर भी इन इंडियन एक्यूसिंग सर्विस अधिकारियों का ही कब्जा है। यथार्थ में ये प्रशासनिक और न्यायिक वैधानिक गनडाग्स है। जो पूर्ण रूप से सर्त अधिकार संपन्न होने के कारण घोर जालसाज, भ्रष्ट, महा मक्कार, शासकीय गिद्ध है जो न केवल शासकीय धन और सम्पत्तियों का कम समय में ही अधिकतम दोहन कर हजम कर जाते है। दूसरी और हर शासकीय जिला अधिकारियों के तात्कालीन केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सचिव होने के रूप में नियंत्रक, प्रबंधक, प्रशासक होने के कारण हर किसी से भ्रष्टाचार शासकीय धन में राजस्व संग्रहण में लूट और डकैती में मासिक वसूली में इनका हिस्सा होता है। मंत्रालयों में ये ही हर विभाग के सचिव और प्रधान सचिव होते है। आबंटन, स्वीकृति, नियम कानून, परिपत्र जारी करना आदि सब इन्हीं के संरक्षण में होता है। ये अपनी कमाई के लिये हर तरफ, हर तरह का खेल खेलते हैं और परेशानियां झंझटे, न्यायलयीन प्रकरण संबंधित अधीननस्थों के गले में फंसाकर, खा पीकर, पिछाडू हाथ पोंछ कर स्थानांतरण करवाकर स्किल जाते हैं। पिछले 10 से ज्यादा वर्षों से कार्यपालन यंत्री स्तर के लोक निर्माण विभाग मप्र जल संसोधन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकीय, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, उद्योग केंद्रों, नगरीय विकास प्राधिकरणों तथा इंदौर विकास प्राधिकरण, देवास वि.प्रा., उज्जैन वि.प्रा., जबलपुर वि.प्रा., ग्वालियर, भोपाल वि.प्रा., लोक स्वास्थ यांत्रि., प्र ग्रह निर्माण मंडल, नगर निगमों पालिकाओं द्वारा सड़कों, नहरों, बांधों, परियोजनओं, कालोनियों, औद्योगिक क्षेत्रों आदि के लिये किसानों, नागरिकों से जो भूमि अधिग्रहित की जाती है। संबंधित विभाग जिले की भूमि की निर्धारित कीमतों के साथ भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के लिये जिलाधीशों को लिखता है, कुल बताई गई कीमत के साथ 10 प्रतिशत खर्च के साथ संबंधित भूमि अधिग्रहण करने के लिये जिलाधीश के पास कुल राशि का चेक जमा करवा दिया जाता है। राज्य सरकारों के कार्यालयों के साथ ही केन्द्रीय मंत्रालय के विभाग भी भूमि अधिग्रहण के लिये यही प्रक्रिया अपनाते हैं। इस में साथ में लोक निर्माण विभाग अधिकारी के जिले के संभागीय अभियंता को शामिल कर उसे मध्यस्थ एजेन्सी का दायित्व सौंपा जाता है, परंतु ये धूर्त जिलाधीश उनके सहा. उप व सहा. जिलाधीश अधिकारी भूमि अधिग्रहण में ओने-पौने क्षतिपूर्ति का भुगतान कर सारा पैसा हजम कर जाते हैं। इस क्षति पूर्ति के वितरण में हर कदम भारी जालसाजियां की जाती है, जिनकी शुरूआत सर्वे से होती है, असिंचित भूमि की क्षतिपूर्ति कागजों में सिंचित की जाती है। झाड़ियों को पेड़ों में फुलदार और कीमती पेड़ों के रूप में, झौपड़ियों को पक्का मकान के रूप में सरकारी रिकार्ड में चढ़वाने के लिये भूमाफियाओं से सर्वे करने वाले अधिकारी-कर्मचारी ही मोटी वसूली कर डालते हैं। दूसरी और सिंचित-असिंचित कृषि भूमि का मुआवजा शासन टीकमगढ़ की कीमत इंदौर में भी 20 लाख रु. प्रति है, का भुगतान देता है, जबकि वहीं शासन भूमि की खरीदी-बिक्री की हर गली-मोहल्ले के हिसाब से गाइडलाइन न केवल तय करता है व हर साल उसमें 10-20 प्रतिशत बढ़ोत्तरी करता है और उसी हिसाब से स्टॉम्प ड्यूटी की वसूली करता है। जिस गाइड लाइन से स्टॉम्प ड्यूटी की वसूली करता है उन्हीं दरों से अधिग्रहण में क्षति पूर्ति का भुगतान किया जाना चाहिये, पर वह तत्काल में नहीं होता बाद में भूस्वामी जब प्रकरण न्यायालय में लगा देते है तो पांच दस वर्ष सत्र एवं जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से बाजार दरों पर भुगतान के आदेश होते हैं।

ऐसे 90प्रतिशत प्रकरणों में जिला न्यायलयों से लेकर ये मामले में सत्र न्यायालयों से लेकर सर्वोच्च न्यायालयों तक ये कार्य विभागों यथा लोक नि. जल संसाधन, ग्रा.म. से ला. स्वा. या, ग्रह नि.म., वि.प्राधि, क्षेत्रीय नगरीय जबकि जिलाधीश कार्या. को अग्रिम भुगतान कर देते हैं। तब भी ये जिलाधीश के सहा., उप, स्वयं जिलाधीश भू-अधिग्रहण की कार्यवाही, भुगतान, गजट नोटिफिकेशन, विज्ञापन आदि स्वयं करते है। तो ऐसे सारे मामलों में लो. नि.वि. आदि के का.य. के नाम से ही सारी क्षतिपूर्ति के प्रकरणों को लगाया जाकर घोर न केवल मानसिक प्रताड़ना न्यायलयों के साथ विभागीय स्तर पर भी मिलती है, न्यायालय के फोटोकॉपी के खर्च से लेकर सारे वकीलों की फीस व अन्य सभी खर्च अपने जेब से करने पड़ते है। इस बीच अधिकांश प्रकरणों के फैसले निचली अदालतों से भू स्वामी के पक्ष में जाने पर इन का.यं. और इनके स्टॉफ के विरूद्ध कुर्क वारंट जारी होते हैं। जिनकी तामीली भी तहसीलदार जो कि जिलाधीशों के ही प्रति निधि होते है के माध्यम से ही कराये जाते है। स्वयं ही अपने वरिष्ठों की गलतियों, जालसाजियों, अवैध वसूली को नजरअंदाज करते हुये संबंधित अधि.कुर्म. के घर पर उनका ही सामान बंटोरने पहुंच जाते है। शाम 8 बजे, जबकि सारे खेल असली खिलाड़ी धन हजम करने औने-पौने भुगतान जमीन नाप-जोर भी यही करते है। भुगतानों के चेक काटना, भू, मकान जमीन, सिंचित, असिंचित, लंबाई, चौड़ाई इन सबका मूल्यांकन कर भुगतान करना आदि, परंतु न्यायलयों में खड़े होने, मुकदमें लड़ने के लिये कार्यपालन यंत्री, जबकि ये इंजीनियर है, ताकि वकील, उसका काम निर्माण करना और उनका रख रखाव करना हैं, पर ये जिलाधीश और इसके सहा. उप जिलाधीश से सब राजस्व अधिकारी जमीनों में क्षतिपूर्ति भुगतान, कानूनों का पालन ही इनका काम है। जिसका अलग से 10 प्रतिशत खर्च मिलने के बाद भी सारी जालसाजियां इनकी मुकदमें लगाने के लिये भी इन्हीं के कार्यालय के लोक भूस्वामियों को भड़काकर मोटा मुआवजा पाने के लिये भी ये ही न्यायालय भी भिजवाते है। जब प्रकरण न्यायालय में जाते हैं, पक्षकार के रूप में का.य. लोक र्मिाण लो. स्वा. यांत्रिकी, जल संसाधन व अन्य को बना कर सारे दिन न्यायालय में खड़ा करवा दिया जाता है। अकेले इंदौर में इन विभागों के कार्यपालन यंत्रियों पर जिसमें 300 से ज्यादा का . यं. रा.रा., 300 लगभग का.य.लो.नि.वि.स.क 300 पर स.क., जल संसाधन पर 200 प्रकरण, हालात यह है कि का.यं.सं.क.2 में लो.नि.वि. में इतने मुकदमों के कारण आना ही नहीं चाहता। किसी मजबुरी में आ भी जाये तो वही आरएस लेना पसंद करता है, फिर किसी भी कार्य विभाग में न तो विभागीय वकील, विधि सलाहकार। निचली अदालतें और उच्च न्यायलयों में कदम-कदम पर हर किसी को पैसा चाहिये तो ये अन्य झूठे फोटोकॉपी के बिल पास करके इन सबको भुगतान करवाये जाते है। तब ऐसे मुकदमों में बहस हो पाती है। यही हाल शासन के विधि विभाग के हैं। बिना वजन के सरकारी मुकदमों फाइलें एक टेबल से दूसरी पर नहीं जाती, जबकि हर जिले के हर कार्य विभाग की यही हालत है। आखिर इन कार्यपालन यंत्रीयों को इन कानूनी झमेलों में क्यों उलझाया जाता है, जबकि भूमि अधिग्रहण से उनका कोई लेना देना नहीं, फिर जिन्होंने भूमि अधिग्रहण में माल बटोरा है, तो ही ऐसे मुकदमें लड़े। और मुआवजे में से भी हिस्सा खा गए।

### किराये की टेक्सियों के नाम पर हर विभाग लगा रहा करोड़ों का चंदन

# स्पष्ट निर्देशों के बाद भी टेक्सियों का मनमाना भुगतान

**अधिकांश टैक्सियों हर विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की**

म.प्र. में जब सभी शासकीय विभागों में उपयोग किये जाने वाले वाहनों के ईंधन, रख-रखाव के नाम पर अत्यधिक भ्रष्टाचार और लूटपाट होने लगी, वर्षों से खराब एक ही स्थान पर खड़े वाहनों में ईंधन मरम्मत के नाम पर अधिकांश विभाग जिसमें कलेक्टर कार्यालयों से लेकर म.प्र.लो.नि.वि., जलसंसाधन विभाग, कृषि, महिला बाल विकास, ग्रामीण यांत्रिकीय, पुलिस, तहसीलों, मत्स्य, सहकारिता, स्वास्थ्य, न.घा.वि.प्रा., निगमों और निकायों में भारी भ्रष्टाचार हो रहा था में तब किराये की टैक्सियों की टैक्सियां लेने का निर्णय हुआ। बाकायदा टैंडर बुला कर दिया जाना चाहिये पर अधिकांश हर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी ही टैक्सियां ऊंची मासिक किरायादारों पर लगा रखी हैं। जहां रु. 300 से 600/- प्रतिमाह होनी चाहिए वहां न्यूनतम रु. 600 से 850/- प्रति दिन किराया चुकाया जा रहा हैं, जबकि वित्त विभाग का परिपत्र क्र. 1-16/2012 नियम चार भोपाल दिनांक 6/10/12 यह है-

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय भोपाल
क्रमांक : एफ 11-16/2012/नियम/चार
भोपाल, 6 अक्टूबर, 2012

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त कमिश्नर,समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।

विषय - विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा वाहन किराये पर लिए जाने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त।

संदर्भ - वित्त विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2006/नियम/चार, दिनांक 24-6-2006 एवं परिपत्र क्रमांक एप 3-1/2007/नियम/चार, दिनांक 26/10/2007

शासकीय कार्यों के संदर्भ में विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा विभाग में वाहनों की कमी के चलते, मासिक आधार पर वाहन किराये पर ली जाती हैं। मासिक आधार पर वाहन किराये पर लिये जाने हेतु शासकीय धन के उचित उपयोग एवं एकरूपता की दृष्टि से संदर्भित निर्देश प्रसारित किए गये हैं। शासन के ध्यान में आया है कि शासकीय कार्य हेतु निजी वाहन किराये पर लिए जाने पर विभिन्न कार्यालयों/विभागों द्वारा अलग-अलग प्रक्रिया अपनाई जा रही है। 2/ अतः वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2006/नियम/चार, दिनांक 24-6-2006 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2007/नियम/चार, दिनांक 26/10/2007 को निरस्त करते हुए शासकीय कार्यों के संदर्भ में विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा मासिक आधार पर वाहन किराये पर लिये जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:-

(शेष पेज 6 पर)

### नर्मद्र भ्रष्टाचार घाटी विकास प्राधिकरण- इंजीनियर व ठेकेदार कर रहे अरबों की लूटपाट

# नर्मदा क्षिप्रा लिंक प्रोजेक्ट- झूठी वाहवाही का पुलिंदा

**30 माह का कार्य 90 माह में भी पूरा नहीं, भ्रष्टों और निकम्मों की फौज, ठेकेदारों की कठपुतली कर रही अरबों रु. की बर्बादी, मुअ. से उपयंत्री तक सबकों लूट से मतलब**

मप्र शासन ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण और उसकी योजनाये बांध, नहरों में लाखों-करोड़ों के निवेश से जनहित साधन के नाम पर हर सरकार के लिये 1980 से वर्तमान तक उसके मुख्यमंत्री , सिंचाई या जल संसाधन मंत्री, नर्मदा घाटी मंत्री, उपाध्यक्ष, प्राधिकरण के सदस्य, अभियांत्रिकीय, मुख्य अभियंताओं से लेकर बड़े बाबुओं और अधीक्षकों तक के लिये सतत दूधार गाय रहा और रहेगा, यहां पर भी अधिकांश सदस्य इंजिनियरिंग से लेकर सभी संभागीय कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर जल संसाधन विभाग से आये उपयंत्रियों तक ऐसे निकम्मों और भ्रष्टों की फौज को बैठाया गया जो आंख मींच कर ठेकेदारों की हां में हां करते हुये नाप पुस्तिकाओं को भी ठेकेदार के कर्मचारियों तक से भरवा कर हस्ताक्षर करता रहा, यहां पर भी किसी को भी समझदार, होशियार और ईमानदार उपयंत्रियों से लेकर सहा. यंत्रियों, कार्यपालन यंत्रियों, अधीक्षण यंत्रियों, मुख्य अभियंताओं और सदस्य अभियांत्रिकीय की आवश्यकता नहीं थी।

हाल ही में मप्र जल संसाधन विभाग से पदोन्नत होकर अ.य. से मुख्य अभियंता एस.एम.जैन को नया वि.प्रा. में प्रति नियुक्ति पर पदस्थ किया गया। जब उन्होंने रु. 36 करोड़ का एक फर्जी बिल पास करने से मना कर दिया तो ठेकेदार और सदस्य अभियांत्रिकीय महाधूर्त इंगले व मंत्री के.एल. अग्रवाल ने तत्काल वहां से हटाकर उनकी सेवाये पुनः जल संसाधन विभाग को सौंप दी।

दूसरी और सदस्य अभि. के रूप में बैठाये गये इंगले का इतिहास जब ये हरामखोर जालसाज रतलाम का पं. जल संसाधन विभाग था, अपने ही स्टॉफ का जीपीएफ का पैसा निकाल कर हजम कर गया था। वह जांच शायद आज तक लंबित है। विभागीय जांच से बचने और अपने प्रकरणों को ठंडा करने की नियत से वहां से नपा विप्रा सं.क्र. 32 में यं. प्रतिनियुक्ति पर आया। यहां पर ओकारेश्वर बायीं तट नहर प्रथम चरण 9.775 किमी से 18.92 किमी में भराई में काली मिट्टी से भराव किया गया जिसमें मापदंडों के अनुसार पीली मिट्टी की भराई कर उसे हर एक मिट्टी डालकर पानी के छिड़काव कर दबाया जाना चाहिए था। इसके विपरित काली मिट्टी के भराव कारण 1.5 फुट से 2.5 फुट चौड़े और 15-20 फुट लंबी दरारों के बाद भी उस पर पुनः उसी काली मिट्टी की भराई करवाकर अंदर 10 सेमी के स्थानपर 6से 7 सेमी ३:६:९, सीमेंट , बजरी, गिट्टी की कांक्रीट के स्थान २:५:९ के अनुपात का किया गया। वह शुरुआत भी 30माह अर्थात जनवरी 09 में 30 के अनुबंध की अवधि समाप्त हो चुकी थी, जब 30 माह की अनुबंध की अवधि थी, उसके कार्यादेश मिलने के महीनों बाद शासकीय वन विद्युत रेलों लाइन, भू अधिग्रहण आदि को सूचित कर कार्यवाहियों को विलंब से ही प्रारंभ किया गया, जबकि तुरंत बाद सारी कार्यवाहीयां पूरी करना चाहिये थी। 59 किमी में कार्य भी हर 5 किमी के खंडों में एक साथ शुरू होना था, जो जानबूझकर कीमतों में वृद्धि का लाभ उठाने की बदनियती से नहीं किया, उस वक्त तात्कालीन का.यं. इंगले इस करण सिंह की कठपुतली बन उसकी ही गाड़ियों में घुमता था। इस प्रकार पहला विस्तार 03.11.08 से 02.07.03 तक, दूसरा 03.07.09 से 31.12.09 तक, तीसरा 01.01.10 से 31.12.10 पूरे 1 वर्ष का, 4 था 01.01.11 से 30.06.11, 5वां 01.07.11 से 31.03.12 तक, 6वां 01.04.12 से 31.03.13 पत्र क्रं. 403832/सा./ओंकार/फेस/408-03-2385 दि. 15.06.12 सदस्य इंजिनियरिंग द्वारा 7 वां विस्तार 01.04.13 से 31.03.14 तक मुख्यमंत्री कार्या. से दिया गया अर्थात 30 माह का कार्य 90 माह में भी पूरा नहीं होगा, इसके पीछे पूरी लॉबी 32 नं. का का.यं. वृत्त 10 का अ.यं. और मुख्य अभियंता निचली नर्मदा परि. इंदौर से लेकर, सदस्य अभि. भोपाल से लेकर भ्रष्टों और जालसाजों की पूरी गैंग नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण केवल लूटने, खाने के लिये बैठी है। यही हाल टर्न की प्रोजेक्ट का रा.अ. बाई सागर बरगी डेम की नहरों से लेकर नीचे कि नं. परि. इंदिरा सागर नहरों तक हर मुख्य अभि. का है।

इंदिरा सागर नहरों के मु.अ. सनावद से सूचना के अधिनियम में निरीक्षण रिपोर्ट की जानकारी मांगी गई थी, हरामखोर मुं.अ. न.घा.वि.प्रा. ने यह कहकर पत्र का जवाब दिया कि का.यं. से मांगों, स्पष्ट है कि हरामखोरों की फौज सारे भ्रष्टों, जालसाजों को अपनी कमाई के लिये बचा रही है और खुद बच रही है।

नर्मदा, क्षिप्रा लिंक परि. को लेकर भी जैसा कि मुख्यमंत्री शिवराज चारों ओर शिगूफा फैला रहे हैं। उसके पीछे का सच यह है कि उसका पानी सिमरोल से ही पीथमपुर की तरफ मोड़ कर पीथमपुर की फैक्ट्रीयों को पानी देने के लिये भी किया जा रहा है। पाइपलाइन वहां पहुंचने के पहले ही 15-20 फैक्ट्रीयों के आवेदन स्वीकृत कर लिये गये हैं, ताकि उद्योगमंत्री कैलाश विजयवर्गीय की विषपोषित फैक्ट्रीयों को पानी दिया जाकर उनको लाभांवित किया जा सके, दूसरी और इसमें उपयोग किये जा रहे 3770 पाइप 12 फुट लेने 1.5 भी डाला, पानी नर्मदा से जिस उज्जैनी गांव के क्षिप्रा उदगम स्थल पर डालेंगे वहां से आगे 4 किमीतक क्षिप्रा के बहाव स्थल क्षेत्र में पिछले 20 से ज्यादा वर्षों से खेती की जा रही है, अर्थात मेघा इं. प्रा.लि. ने 364 दिन में जिसमें अब मात्र 3 माह बचे हैं। तो बहाव स्थल ही नहीं है, तो उस गांव के चारों तरफ की जमीनों को बर्बाद करेगा, आगे चार किमी स्थल में खुदाई कर उसके बहाव क्षेत्र से जोड़ भी दिया गया तो पहले पानी देवास भी मुश्किल से ही पहुंचेगा, क्योंकि बीच के 30 किमी क्षेत्र के नदी के दोनों तरफ के किसान अपनी कृषि को सिंचित करेंगे, सामने से बहता हुआ पानी कौन छोड़ना चाहेगा और नगर निगम उपयोग कर लेगा। दूसरी तरफ सिहंस्थ 12 वर्ष में 3 माह, फर, मार्च, अप्रैल में होता है, 11 वर्ष 9 माह तो दूसरे अन्य सभी उपयोगों में आयेगा, तीसरी तरफ वर्तमान में प्रति माह रु. 2 करोड़ की विद्युत कहां से आयेगी, जब अभी प्रदेश की 7.25 करोड़ जनता के घर रोशन नहीं हो पा रहे, फिर इसका खर्च कौन उठायेगा, जिलाधीश, खरगोन, देवास या उज्जैन।

यथार्थ यह है कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में चुनकर एक से बड़े एक भ्रष्टों, नकारा, निकम्मों की फौज, जिसमें सदस्य अभि. विद्युत, वन, पुर्नवास वित्त में बैठाने से लेकर अगर इंजिनियरिंग में भी लिया जाये तो केंद्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत ने केवल नहरों की डिजाइन को लेकर माइनर, सब माइनर वितरणी के चित्रांकन को दर निकार कर मनमर्जी से ही अपनी सुविधा, कमाई, भ्रष्टाचार के अनुसार ही सारे भ्रष्ट, जालसाज ठेकेदार जिसमें कर्णसिंग बिहाणी, लड्डाराम, सदभाव इंजिनियरिंग जैसे अन्य कई उपयंत्रियों से लेकर कार्यपालन, अधीक्षण, मुख्य अभियंताओं को टुकड़े डालकर स्तरहीन कार्यों, लक्ष्य से चौगुने, 5गुने समय में कार्य करने बाद भी उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती फिर जालसाजियां सर्वे से शुरू होती है। सर्वे में ही काली मिट्टी कठोर मिट्टी में बदल दी जाती है, अर्थात प्राक्कलन में ही स्तर और खर्च का आंकलन 50 से 100 तक दोगुना कर दिया जाता है। नर्मदा, क्षिप्रा सिहस्थ लिंक परि. में उपयोग किये जा रहे 3770 पाइप×12 मी. - 45.240 मी लंबाई और बड़वाह की अपेक्षा ओंकारेश्वर बांध के भराव क्षेत्र से लेकर सीधे उज्जैयिनी लाया जाकर लगभग 10 किमी की बचत की जा सकती थी, फिर उज्जैयनी के उदगम स्थल से वास्तविक क्षिप्रा के बहाव स्थल के बीच 4 किमी में जब खेती हो रही है, क्षिप्रा का अता-पता नहीं है, तो पानी लाकर क्या उपयोग करेंगे। यहां जालसाजियों औश्र नाकामीयां दोनों ही है। अर्थात सिंहस्थ के शिफूले की आड़ में सिमरोल के तिराहे से सारा पानी पीथमपुर पहुंचा कर उद्योगों को लाभांवित करना ही उद्देश्य है, या फिर नाकामी छिपाने के लिये 4 किमी लंबी नहर खोद कर क्षिप्रा के बहावसे जोड़ेंगे। इससे बेहतर था कि सीधे पाइप लाइन को उज्जैन में ही क्षिप्रा में मिलाते, ताकि 80-90 प्रतिशत पानी का दुरुपयोग भी रोका जा सकता था, देवास के उद्योगों को भी पूरा लाभ मिल पाता, इस से सिद्ध होता है कि किस प्रकार 32 नं. संभाग के का.यं., खेड़ीघाट के अं.य. जो अधिकांश संविदा पर ही रहे हैं, जालसाज, निकम्मे मु.अ. जो है तो अधीक्षण यंत्री पर पिछले लंबे समय से मु.अं. का पद संभाल रहे हैं। सैकड़ों करोड़ की इस जालसाजी में अनेकों को निर्लंबित कर आरोप तय किये जाने चाहिए पर सबका उद्देश्य काम की आड़ में मोटा धन हजम करना ही हो तो कौन किसकी बोलेगा, फिर मु. अभि. अजकरे जो अ.यं. है पर मुख्य अभियंता भी संभाल रहे है। पुराना का.यं. के काल अं.यं. काल का इतिहास निकम्मेपन और भ्रष्टाचार से ही पूरा भरा पड़ा है, इसके हाथ में वर्तमान में रु. 1500 करोड़ से ज्यादा के टर्न की परियोजनाये जिसमें मानजोबर की नहरे, ओंकारेश्वर की दायी-बांई तट की नहरें और नर्मदा क्षिप्रा लिंक में कुल भुगतान का 27 भी मिला तो रु. 5 से 10 करोड़ हजमकर रहा है, केवल बैठने और मु.अ. की नौटंकी करने का।

## हर क्षेत्र में जापानी सहयोग लेकर दो चीन को सबक

( पेज 1 का शेष )

जापान की कंपनियों ने ही चीन को हर क्षेत्र में औद्योगिक स्तर पर विकसित किया है, अधिकांश इलेक्ट्रानिक्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स जापानी कं. के सहयोग से ही निर्मित कर पूरे विश्व को चीन आपूर्ति कर विदेशी मुद्रा कमा रहा है, जबकि चीन और जापान एक-दूसरे के सदियों पुराने चिर शत्रु हैं। जिसके प्रमाणित समाचार पूरे विश्व के मुद्रित और दृश्य प्रसारण में प्रमुखता से स्थान पाते हैं। जापानियों का नाम सुनते ही चीन और चीनी सरकार व जनता भड़क उठती हैं पर जापानी बड़ी शीतलता से सटीक जवाब देता हैं, जापानियों की राष्ट्रभक्ति पूरे विश्व में बड़ी श्रद्धा से देखी जाती हैं, यही राष्ट्रभक्ति उनकी सामरिक क्षेत्र में श्रेष्ठता प्रदान करती हैं, उनके युद्ध कौशल से न केवल चीन वरन अमेरिका और ब्रिटेन अभी भी चमकते हैं। इसी कारण से द्वितीय विश्वयुद्ध में जापानियों का मनोबल तोड़ने के लिये अमेरिका ने जापान के दो बड़े महानगरों हिरोशिमा और नागासकी पर परमाणु बमों सेहमला कर दिया था, इसके पूर्व में जापानियों ने अमेरिका के दो बड़े बंदरगाह, जो अमेरिका की जलसेना के खास अड्डे थे नष्ट कर दिये थे। उससे अमेरिका का बुरी तरह घबरा गया था, अर्थात जापानियों नेपहले अमेरिका के दांत खट्टे कर दिये थे, जापानियों का दो सौ वर्षों से ज्यादा समय तक चीन पर कब्जा रहा है, इस इतिहास को चीनी भुला नहीं पाते हैं। इसलिये ही चीनी सरकार और जनता जापान का नाम सुनते हीभड़क उठते हैं। कांटे से ही कंटकों को निपटाया जा सकता हैं, जब बचाव से काम न चले तो आक्रमण की नीति अपनाना जरूरी है। भारत के भ्रष्ट और हरामखोर सत्ताधीशों को स्वार्थों से परे, चीन से जुड़ी 4000 कि.मी. सीमाओं की रक्षा के लियेजापानी सेना सेयुद्ध कौशल का लगभग 50 लाख सैनिकों को प्रशिक्षण देना चाहिये, ताकि न केवल चीन वरन् पाकिस्तान से जुड़ी 2500 कि.मी. सीमा जो आजाद काश्मीर से लेकर पंजाब, राज. और गुजरात तक फैली है सीमाओं को चुस्त-दुरुस्त रखा जा सके, उनकी जलसेना से युद्ध कौशल का प्रशिक्षण लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तटीय आंध्र, केरल, तमिलनाडु, ओड़िसा, बंगाल तक की जलीय सीमाओं की सुरक्षा के साथ चीन, पाकिस्तान, लंका के साथ ही बंगलादेश तक को समय रहते सबक सिखाया जा सके। पर ये सब तब ही संभव होगा जब हमारे धूर्त, मक्कार, कमीशनखोर सत्ताधीश चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाल से गुप्त रूप से कमीशन, भ्रष्टाचार से कमाई पर अंकुश लगा पाएंगे, इस भ्रष्टाचारी मानसिकता के कारण भारत की इज्जत नहीं की जाती। अनेकों जापान कं. जिसमें सोनी अकाई सेमसंग एलजी आदि इलेक्ट्रिकल्स और आटो मोबाइल कं. वस्त्र, खिलौने, कंप्यूटर्स आदि का उत्पादन भारत में कर रही है, जबकि अभी भारी मशीनरीज जिसमें टेक्सटाइल, आटो के साथ अनेकों कई कं. को आमंत्रित किया जा सकता है। तत्काल में भारतीय सैनिकों का जापानी अनुशासन कर्मठता के साथ जुनून पैदा करना जरूरी हैं, इसके विपरीत हमारे भारतीय पाकिस्तान से कमीशन और विश्वतखोरी कर रहेहैं, तो ये सारी बातें और तथ्य निरर्थक ही सिद्ध होंगे।

## उत्तराखंड की भीषण तबाही में सत्ताधीश, चीन के साथ

( पेज 1 का शेष )

जिससे उत्तरकाशी और कैदारनाथ में भयानक बाढ़ से चारों तरफ भारी तबाही मची, जिससे मुख्य सड़के बह गई, हजारों पेड़ और जंगल साफ हो गये, लाखों व्यक्ति जिसमें पूरे देश के राज्यों से पहुंचने वाले लाखों तीर्थ यात्रियों की जीवन लीला समाप्त हो गई, तब भी कांग्रेसी मा. राहुल गांधी, प्र.म. मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी अपनी श्रेष्ठता और राष्ट्रायपक्ष होने का हवाई अड्डों पर शक्ति प्रर्दशन करते रहें, क्योंकि ये सब षड़यंत्र का हिस्सा थे, जिसके अंतर्गत वहां से हिन्दुओं को पूर्णतः साफ करना था। समय माया डॉट काम की साइट पर इसे षड़यंत्र की बात लिखी गई जिसमें बादल फटने और भारी वर्षा से प्राकृतिक आपदा के तथ्य को सिरे से नकारा था। 23 जून 13 के बाद भारतीय दूरस्थ संवेदन संस्थान ने भी अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि वहां कोई बादल फटने की घटना 14,15,16 जून को नहीं घटी। इसके पूर्व 23 मई 2007 या 08 में भी हिमाचल में भरी गर्मियों में भी इन हिमनदों को पिघलाकर हिमाचल में बाढ़ का कहर ढाया गया था, तब भी शिमला के आस-पास के क्षेत्रों में भारी बाढ़ आ गई थी। चीन ने सन 2000 के पूर्व से ही हिमालयके भारत की और प्लान क्षेत्रों में बड़े-बड़े गड्डों और पहाड़ी की दरारों में बर्फ जमाने और पिघलाने की सैन्य तैयारियां कर ली थी, जिसके बारे में भारतीय सेना, रक्षा और ग्रहमंत्रालय को बराबर सूचित करती रही हैं पर हमारे धूर्त सत्ताधीशों का एक मूल मंत्र है- देश बर्बाद हो या आबाद, देश से लूटों, विदेशी बैंकों में जमा करो, आपदा आये तो चुपचाप खिसक लो। भारतीय सत्ताधीशों के जो संबंध पाकिस्तानी आईएसआई, दाउद से पिछले 20-30 वर्षों से रहे हैं। वही संबंध आंतरिक तौर पर चीनी शासकों से भी हैं। यही कारण है कि जब-जब कोई मंत्री, सचिव विदेश चीन जाता है तब ही चीन ज्यादा घुसपैठ करता है। वही हाल उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ के ठीक पहले सलमान खुर्शीद चीन यात्रा पर गया था, शायद वह इसी षड़यंत्र को अंजाम देने गया था कि पूरे उत्तरांचल के उत्तरकाशी, काशीपीठ, कैदारनाथ, जोशी मठ में जो हिन्दुओं और उनके तीर्थों, मंदिरों का जमावड़ा है, इसे साफ कर दो, फिर ही तुम आसानी से कब्जा कर पाओगे। वहां के साधु-संत भी यही कहते है कि जिस दिन हमने यहां से पलायन किया चीनी और पाकिस्तानी कब्जा कर लेंगे, इस यथार्थ की पुष्टि करते है। दूसरी तरफ हम देखें कि आर्थिक स्तर पर हमारे सत्ताधीशों ने देशी उत्पादकों चाहे वह इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिानिक्स, रसायन, वस्त्र उद्योग, रेशम, प्लास्टिक, दवाओं, खिलौने, फटाकों आदि को नष्ट करने के लिये भारी भरकम टैक्स, विद्युत आदि की भारी परेशानियां देकर अधिकांश उद्योग नष्ट कर दिये वहीं सारा माल भारतीय बाजारों में चीन का भरा पड़ा है, जो 80 से 95 प्रतिशत तक सारा माल दो नंबर में आता है, जिस पर न तो केन्द्र सरकार को और न हीं राज्य सरकारों को कोई टैक्स मिलता है, न ही जनता को रोजगार। जबकि दूसरी और चीन की अर्थव्यवस्था के फलने-फूलने में भारतीय बाजार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है।

सारे चीनी माल से भारतीय सत्ताधीशों को मोटा कमीशन मिल रहा है। जबकि भारतीय बैंकों से हजारों करोड़ रु. प्रतिदिन भुगतान चीन में डॉलर में होता है, जो एक तरफ तो डॉलर की कीमत बढ़ा रहे है दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहे हैं। देशी उद्योगों पर एक ही उत्पाद पर केन्द्रीय एक्साइज विक्रय कर, कच्चे और तैयार दोनों पर क्षेत्रीय विक्रय कर, कच्चे और तैयार दोनों पर अर्थात तैयार माल की कीमत पर 50 प्रतिशत से 200 प्रतिशत तक देश में कर, जबकि विदेशी माल पूरा दो नंबर में बिकने देने के पीछे मोटा कमीशन के अतिरिक्त क्या हो सकता है, जिससे अधिकांश देश के उद्योग नष्ट हो गये या कगार पर है। ऊपर से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो कहां, अर्थात ये कांग्रेसी शूकरों की फौज अपनी कमीशनखोरी के लिये सबकुछ दांव पर लगाकर अपनी नीच मानसिकता का प्रमाण लाखों लोगों की मौत और परेशानियों से हर कदम दे रही है।

साप्ताहिक
समय माया

### मप्र रोड डकैत कार्पोरेशन- निक्कमें, भ्रष्ट, जालसाजों का सरकारी गिरोह

# 50 अधिकारी 5000 किमी सड़कों पर 5 करोड़ वाहनों से कर रहे लूट

## 70 प्रतिशत 2 लेन पर टोल, हर वर्ष 7 प्रति. बढ़ी, जो 3 वर्ष में होना थी

मप्र की 5000 किमी सड़कों पर मप्र रोड डकैत कार्पोरेशन के प्रं.सं. विवेक अग्रवाल से लेकर सारे अधिकारियों को कार्य विभागों में मप्र लोक निर्माण विभाग, मप्र लोक स्वा. यांत्रिकीय, मप्र जल संसाधान निगम आदि से प्रति नियुक्ति पर या सेवानिवृत्ति के बाद संविदा पर चुनकर उन भ्रष्टों और निकम्मों को लाया गया हैं, जिन्हें काम से नहीं दाम से मतलब होता है और जो ठेकेदारों और अपने भ्रष्ट महाजालसाज प्रबंध संचालक और उसकी चांडाल चौकड़ी के इशारो पर नाचते है। जो ईमानदार और काम करने वाले अभियंताओं को ये घूर्त इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारी विवेक अग्रवाल किस तरह से प्रताड़ित और जलील करता है उसका एक उदाहरण है। मुख्य अभियंता आर.के. सांखला जो दो वर्ष इस डकैत कार्पोरेशन में कैसे रहे, कितनी प्रताड़नाये इस बतमीज और उसकी चांडाल चौखड़ी ने इसलिये दी कि वो ठेकेदारों से अच्छे काम करवाने के लिये न कहे, दो वर्ष के कार्यकाल में तो 5 से ज्यादा बार छुट्टियों पर गये और मानसिक आघातों से बीमार हुये। इनकी इस लूट और बतमीजीयों को लेकर भिंड के कांग्रेसी विधायक डॉ. गोविन्द सिंग ने न केवल विधानसभा में प्रश्न उठाये और कहा कि इस निगम के 50 अधिकारी 5000 किमी सड़कों की कैसे देखरेख कर रहे हैं। प्रदेश की 4000 किमी से ज्यादा सड़के बीओटी ठेकेदारों के कब्जे में है जिन्हें इंडियन रोड कांग्रेस के स्तर से न बनाये जाने के बाद भी पूर्णता प्रमाण पत्र देकर जनता वाहन चालकों की सुरक्षा का ध्यान रखे बिना लूट के लिये खुला छोड़ दिया गया है। 1000 किमी से ज्यादा सड़कों पर एडीबी के ऋण या मंडी शुल्क से बनाने के लिये छोड़ दिया गया है। यह इस डकैत कार्प. में चुनकर ऐसे भ्रष्ट, निकम्मों, गुंडागर्दी करने वाले, मक्कार अधिकारियों को प्रति नियुक्ति पर या संविदा पर राज्य के कार्य विभागों से लाकर बैठाया गया है, जो ठेकेदारों की कठपुतली बन उनकी न केवल ज हजूरी करते रहे वरन उनके लिये जनसंपर्क एजेंसी की तरह अपनी सेवाये देकर उनकी साइट क्लियरेंस, शास. विभागों तथा वन विभाग, ग्राम पंचायतों से लेकर जिलाधीश कार्यालय, विद्युत विभाग रेलवे आदि की बाधाएं दूर कर ठेकेदार की परेशानियों को दूर करना है। दूसरी और सारा कार्य यथा डीपीआर बनाने से लेकर सड़क निर्माण देखरेख, उसकी गुणवत्ता स्तर आदि का सारा कार्य वे सलाहकार फर्म कर रही है। जिनमें लो.नि.बि. के उन भ्रष्ट, निकम्मे, चाटूकार सेवानिवृत्ति प्राप्त अभियंता औश्र यंत्री ही विराजमान है, जिन्होंने कभी भी अपने सेवाकाल में ढंग से न केवल काम किया और न करवाया। साथ ही जन-धन से खिलवाड़ कर भ्रष्टाचार से खूब लूटपाट की। जिनमें पूर्व के मु.अ. पीसी अग्रवाल, केसी जैन जैसे पूरेमध्यप्रदेश के पचासों इंजिनियर है, जिन्हें काम गुणवत्ता से नहीं वरन लूट-खसोट से मतलब है। और जितने भी वर्तमान में रोड डकैत कार्पोरेशन में बड़े इंजिनियर उनके हाथ के नीचे कार्यरत रहे है तो वैसे भी वे सलाहकार फर्मे इन्हें कुछ गिनती भी नहीं, अर्थात यहां बैठे सारे इंजिनियर्स का कार्य केवल कठपुतली बन नापना होता है। हर सलाहकार फर्म और ठेकेदार क्षेत्रीय इंजिनियर्स से अपनी तरह कार्य लेता है। बदले में ठेकेदार कुछ खुरचन इन भ्रष्ट श्वानों को डालकर अपने स्वार्थो की सिद्धि करता है। सारे बिल टेंडर, डीपीआर आदि मुख्यालय भोपाल में बैठे घूर्त दोगुनी-तिगुनी कीमत पर देकर अपना मोटा हिस्सा डकारते रहते है। यहीं कारण है कि किसी भी ठेकेदार को एक बार कार्य मिलने के बाद चाहे वह बीओटी, एडीबी, मंडी सेल के अंतगर्त बनाई जाने वाली सड़के है के बारे में कोई भी क्षेत्रीय इंजिनियर बोलता ही नहीं है। स्तरहीन सड़कों पर पूरे प्रदेश में सारे बीओटी ठेकेदार हरामखोरों की फौज तांडव करती रहती है, इसका उदाहरण हर सड़क पर देखने को मिलता है। सबसे पुरानी बीओटी सड़क इंदौर बुरहानपुर को ही ले, यहां बैठे हरामखोर शुकरों की फौज ने दस वर्ष बाद भी न तो किसी टोल पर एंबुलेस-क्रेन खड़ी रखता है, न ही हरामखोर अशोक ब्लिडकॉन कांकरिया नैहर तीन वर्ष सड़कों का पुर्ननवीनीकरण करवाता है। बस गड्ढे भरता और पेंचवर्क कर ये शूकरों का गिरोह अरबों रु. प्रति वर्ष की वसूली हर वर्ष 7 प्रतिशत की दर से कीमते बढ़ाकर कर रहा है। जबकि अनुबंध पत्र में यह शर्त तीन वर्ष में एक बार बढ़ाने की थी। दूसरी ओर 25 वे किमी से 28 वे किमी तक अधिकांश पुलियाओं जिसमें 27/2 किमी दोनों पुलियाओं पर इन डकैतों ने जबकि नीचे 50 से ज्यादा गहरी खाइया है अभी तक उस घाट सेक्शन में 10 वर्ष बाद भी न तो संकेतक लगाए और न ही बेरीकेडस लगा सके है। ये अशोका ब्लिडकॉन के डकैत, दूसरी और सड़क के दोनों और इस घाट सेक्शन में तो 5-5 की पट्टियां ही नहीं भरने की और सड़क के तल से मिलाने की तो बात ही नहीं की जा सकती, परंतु इस 203 किमी मार्ग का 40 किमी समतल सड़कों पर भी इसने वर्षो से पट्टियां नहीं भरी। हर वर्ष 33''/3 प्रति. हिस्से की सड़कों पुर्ननवीनीकरण की तो दूर ढंग से पेचवर्क भी महीनों नहीं किया जा रहा है, क्षेत्रीय इंदौर का संभागीय प्रबंधक टेंटवाल से पूछताछ की गई तो निहायिता ढीला-ढाला यह अधिकारी बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, सारा काम भोपाल से ही किया जाता है। इसका साक्षात्कार यू-ट्यूब पर समय माया के नाम से देखा जा सकता है। वैसे अशोका बिल्डकॉन की जालसाजियों और भ्रष्टाचार का न केवल मुख्यालय में बैठा एमडी विवेक अग्रवाल मुरीद है, क्योंकि इस डकैत की लूट का हिस्सा अग्रवाल को भी मिलता है। इसलिये उसके पास पूरे प्रदेश में सड़क निर्माण और बीओटी के अनेको ठेके है। इस अशोका के पास देवास बाईपास भी है जिसे 4लेन बनाना चाहिये था। चार लेन का भूमि अधिग्रहण भी किया गया, टोल टैक्स भी 4 लेन का ही पिछले 6-7 वर्षो से वसूला जा रहा है, परंतु इस शूकर ने उसे बनाया 2 लेन ही है। जिसका हिस्सा तात्कालीन कलेक्टर, मु.अ. लो.क. उज्जैन ने भी हजम किया। स्वाभाविक है लूटने और लुटाने वालों को ही आई.ए.एस. व अन्य अधिकारी ज्यादा पसंद करते है।

6 वर्षो से ज्यादा समय से उज्जैन मे बैठा संभागीय प्रबंधक सूर्यवंशी टुकड़ेकर भी ठेकेदारों की कठपुतली बन न केवल नाचता है वरन उसका इस संबंध में एक साक्षात्कार जो यू-ट्युब पर समय माया के नाम से लगाया हुआ है। में ये हराम खोर जालसाज इतना बोखला गया कि न केवल कैमरे के सामने से भागा वरन बाद में अपने सहा.यंत्री अशोक शर्मा को भी साक्षात्कार के बाद श्री अजमेरा से कैमरा छीनने और मारपीट के लिये भेजा जो यू ट्यूब पर देखी जा सकती है। इसके अंतर्गत 600 किमी से ज्यादा बीओटी की सड़के हैं जिसमें इंदौर उज्जैन की सड़कों पर ही देखें दोनों वसूली नाकों पर न तो एंबुलेस, न ही क्रेन दिखती है। दूसरी ओर 3 वर्ष से ज्यादा गुजरने के बाद भी सड़क निर्माण के समय जितने पेड़ों की बलि चढ़ाई गई उससे दोगुने पेड़ लगान की कहानी भी फाइलों में दफन है, जहां सड़क सामान्य तल से 5 से ज्याद ऊंची है वहां पर तीन वर्ष बाद भी बेरिकेड्स नहीं लगाये गये है। उज्जैन-झालावाड़ सड़क जो महू के ठेकेदार के पास है। एक तिहाई हिस्से पर पुर्ननवीनीकरण की तो दूर गड्ढों की भराई समय पर नहीं होती है। जब यही बात स.प्र. सूर्यवंशी से साक्षात्कार में पूछ गई तो गुर्रा कर कहा कि बेहतरीन सड़के है। 150 किमी की स्पीड से चलने पर भी पेट का पानी नहीं हिलता है। बाद में अशोक शर्मा को कैमरा छीनने भेजा, जिसकी शिकायत पलासिया थाने में देने के साथ ही मु.मं., मु. सचिव, प्र.स. सब को भेजी गई पर ठेकेदारों के टुकड़खोर किसी भी हरामखोर ने कोई कार्यवाही नहीं की गई। इनकी टुकड़खोरी का ही परिणाम था की धार-नागदा बीओटी के पुल का हिस्सा ही धंस गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये ठेकेदारों और डकैत कार्पोरेशन का गिरोह जन-धन और सीधे जनता के धन लूटने में लगा है। इन हरामखोर संभागीय प्रबंधकों से जानकारी मांगने पर उज्जैन की डकैत गैंग जवाब ही नहीं देती। इंदौर संभाग 1 व 2 जवाब देंगे भी तो आवेदन के अनुसार नहीं और पैसे जमा करने पर मांगो कुछ तो जालसाजों की फौज देती कुछ और अपील भी करों तो उप मुख्य महाप्रबंधक गौतम सिंग ने जवाब ही नहीं भेजा जो कि डिप्टी कलेक्टर की रैंक का है, यहां पर कार्य कर रहे ठेकेदारों गिट्टी पत्थर खोदकर कहीं पहाड़ साफ कर दिये तो कहीं गहरे गड्ढे बना दिये और रायल्टी नाम मात्र की भी जमा नहीं की। इन सबमें दिलीप सूर्यवंशी का नाम पूरेमप्र में सबसे आगे है, जिसके आपराधिक और जालसाजी पूर्ण कृत्यों की कहानी हर दिन समाचार पत्रों में छप रही है। जो मु.मं. कार्यालय से लेकर इस डकैत कार्पोरेशन और लो.नि.वि. के भ्रष्ट धूर्तो का सबसे चहेता है। उज्जैन-इंदौर संभाग से मांगा गया था कि रायल्टी, वेट, सर्विस और आयकर में इन ठेकेदारों ने कितना पैसा जमा किया तो जवाब ही नहीं दिया गया जबकि सरे करों को हर जिले के खनिज अधिकारी और जिलाधीशों को भी टुकड़े डालकर उनका मुंह बंद कर देते है। अन्यथा रतलाम के खनिज अधिकारी संजय लूनावत की तरह ये डकैत कार्पोरेशन के अधिकारी उसको मार डालते हैं। जबकि इस डकैत कार्पोरेशन के एमडी से लेकर संभागीय प्रबंधकों की यह जिम्मेदारी होती है कि वो ये देखें कि शासन की रायल्टी व अन्य करों को वह ठेकेदार जमा कर रहा है या नहीं अन्यथा उस पर ठेका रद्द करने की कार्यवाही भी की जा सकती है, परंतु ये टुकड़खोर ठेकेदारों द्वारा फेंके गये टुकड़ों को चबाने में ही इतना मस्त रहते हैं कि कानूनों का पालन करवाने का होश ही नहीं रहता। पाठकों की जानकारी के लिये बता दें कि ये डकैत कार्पोरेशन पूरे प्रदेश 60 प्रतिशत से ज्यादा सिंगल और टू लेन पर जो वसूली कर रहा है, पूर्णतः अवैध है क्योंकि भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय के परि. अनुसार 4 लेन से कम किसी सड़क पर टोल टैक्स वसूली की व्यवस्था ही नहीं है।

## बढ़ता डालर... काले धन वालों को भारत

( पेज 1 का शेष )

वह तो अपनी कमाई के लिये जनता को परेशान करेगी। ये उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य हैं, इसमें नया कुछ भी नहीं। स्व. इंदिरा का नारा था सरकारी सपत्ति आपकी अपनी है, तो यह वाक्य जनता के लिये था कि आपकी अपनी है कि तरह सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा करें और ख्याल रखें, पर सरकारी अधिकारी, नेता और कर्मचारियों के लिये था, सरकारी संपत्ति आपकी अपनी हैं, बेचकर, गिरवी कर, पट्टे पर देकर संपत्ति बटोरिये और ले जाइये, चीटांबर और उसकी कांग्रेस सरकार के महाभ्रष्ट, जालसाज गिद्ध मनमोहन से लेकर हर मंत्री मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ राज्य सरकारों के भी सभी मुख्य व सभी मंत्री व अन्य अधिकारी-कर्मचारी चाहे तो कांग्रेस सरकार के हो या भाजपा, सपा, तृणमूल, डीएमके, जद (यू), जद (बीजू) सब भी यही कर रहे हैं। पूंजीपतियों और उद्योगपतियों से मोटा कमीशन बटोरकर सरकारी संपत्तियों तथा बिजली, सड़कें, पानी, जमीनों आदि तक को निजी क्षेत्र में सौंपकर लूटने में लगे हैं। उसमें चाहे फिर हीरे की खदानें हों या कोयला या गिट्टी, मिट्टी, रेती, पत्थरों की खदानें तक सब शामिल हैं। स्व. इंदिरा गांधी ने जिन पूंजीपतियों की 27/7/1969 को 27 बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर जनता के धन को जनता के लिये उपलब्ध करवाया था, वर्तमान कांग्रेस सरकार पूंजीपतियों की कठपुतली बन उनसे कमीशन डकारने के लिये रिजर्व बैंक व अन्य सभी सरकारी बैंकों में पड़े धन को अपने बाप की जागीर समझ उन पूंजीपतियों को धन उपलब्ध करवान की नियत से चीटांबर वकील होने के नाते छोटे-छोटे परिपत्र जारी करता रहा है। उसकी हर चाल जनता को लूटने वाली और पूंजीपतियों के पोषण के काम आती है, एक तरफ राष्ट्र का वित्तमंत्री, दूसरी तरफ वेदांता, रिलायंस, टाटा, वॉलमार्ट, आई.टी.सी., हिन्दुस्तान लीवर जैसी अनेकों देशी-विदेशी बहुराष्ट्रीय कं. का वित्तीय प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सलाहकार, अरबों करोड़ रु. का कमीशन बटोरकर उनके पक्ष में कानून, परिपत्र जारी करना उसके बायें हाथ का काम रहा है।

चिटफंड कं. के लाखों करोड़ के पूरे राष्ट्र में होने वाले घोटाले में कोलकत्ता में इसकी पत्नी की भी हिस्सेदारी पाई गई, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद स्व. राजीव गांधी चूंकि न तो राजनीति में परिपक्व थे, न ही प्रशासन चलाने में उनकी आड़ में उनके भोलेपन का नाजायज फायदा उठाकर आत्यधिक शातिर, चालक इन दक्षिण भारतीय नेताओं, जिसमें स्व. नरसिंहाराव, चीटांबर ने इन चिटफंड कं., प्लांटेशन, हाउसिंग, फायनेंस कं. का जाल फैलाकर करीब 40,000 कं. ने भारतीय और विदेशी जनता का लगभग रु. 40 लाख करोड़ से ज्यादा हजम कर लिया था, जब म.प्र. के पुलिस अधिकारी हैदराबाद तक पहुंचे और वहां पूछताछ की तो हर किसी अपराध के पीछे शातिर दिमाग चीटांबर ही पाया गया।

वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन जो भूतपूर्व रिजर्व बैंक का गर्वनर रह चुका है। भारतीय स्टेट बैंक और सहायक व अन्य सरकारी बैंकों द्वारा वित्त पोषित किये गये सभी बड़े अरबपति पूंजपतियों और उद्योगपतियों द्वारा लिये गये अरबों रु. के ऋणों को डुबाने और उनकी भरपाई करने के लिये बैंकों द्वारा आम ग्राहकों से लिये जा रहे रु. 500/- के चेक रिटर्न शुल्क, रु. 500 प्रति पन्ने का शुल्क, संधारण शुल्क, गारंटी, मांगपत्र शुल्क, चेकबुक शुल्क आदि इसलिये अत्याधिक बढ़ा दिये गये ताकि बैंकों की जालसाजियों में डुबाये गये शुल्क की भरपाई की जा सके, दूसरी तरफ देशी-विदेशी कार उत्पादकों से मोटा कमीशन डकारकर ऋणों पर ब्याज दर कम की गई, गृह ऋणों में जालसाज भूमाफियाओं, कालोनाइजरों से मोटा कमीशन डकारकर गृह ऋणों पर ब्याज दर कम कर दी गई, ताकि इनका माल बिक सकें, साथ ही रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों में जमा धन को बाप की जागीर मान इन बैंकों को भूमाफियाओं, कालोनाइजरों को उनकी संपत्तियों के पुस्त मूल्य पर 70% तक ऋण देने की भी छूट इसीलिए दी गई, ताकि इन भूमाफियाओं, कालोनाइजरों जिनकी पकड़ प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों से लेकर जिलों के कलेक्टरों, तहसीलों के तहसीलदारों और गांवों के पटवारियों तक होती है, आसानी से धन उपलब्ध करवाकर इन संपत्तियों की खरीद बिक्री पर मोटा लाभ कमाया जा सके और न भी कमाया जा सके तो धन डूबे तो बैंकों में जमा जनता का धन जायें। इसके साथ ही वर्तमान में और भूत में जब से इन जालसाज दक्षिण भारतीयों खासतौर पर चीटांबर का दबदबा प्रधानमंत्री कार्यालय पर बना तब से न केवल रिजर्व बैंक वरन् हर सरकारी बैंक, बीमा कं. पर गवर्नर अध्यक्ष और प्रबंध संचालक के पदों पर अधिकांश दक्षिण भारतीयों को ही अरबों रु. की रिश्वत लेकर स्थापित कर दि गया है ताकि इसकी हर चाल और लूट के खेल को वो सफल करते रहें।

पूरे भारत में किसानों की कर्ज माफी के नाम पर जो हर वित्तीय बजट में राशि दी जाती हैं, उस राशि का 50% से ज्यादा भ्रष्टाचार में डूब जाता है, किसान वीं के वहीं कर्ज में बना हुआ है। जैसा कि समयमाया ने पूर्व में भी लिखा था कि यह ऋण जो कृषकों की ऋण माफी के लिये प्रावधानित है, केवल उन्हीं के खातों में पहुंचेगा जो इस ऋण का 25% इन बैंकरों पर रिश्वत के रूप में बैंकरों को देंगे, अन्यथा इस धन की बंदरबांट होकर हजम कर लिया जावेगा और हुआ भी वही। इसी चीटअबर ने 200 से ज्यादा नये बैंकरों को लायसेंस देने की घोषणा के पीछे भी यही राज है कि ये सभी निजी बैंकर आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस व अन्य सभी शासकीय बैंकरों की तरह विदेशों में

## त में लाने पर फायदा

जमा धन को भारत लाने और ले जाने में मध्यस्थली भूमिका निभाकर काले धन को जमा करने उस धन का पूंजीपतियों के हित साधनों से लेकर अरबों रु. के घोटालों और गबन के अड्डे बनकर गरीबों का पैसा हजम कर दिवालिया घोषित हो जायेंगे, साल दो साल बाद जब परिसमापक बैठेगा रु. की चवन्नी वापस करेगा। इन सब कांडों रु. के बाजारु अवमूल्यन कर कालेधन को लाने कालेधन वालों को लाभ पहुंचाकर कमीशन डकारने आदि के कांडों में राष्ट्रीय स्तर पर कभी बलात्कार, कभी क्रिकेट के सट्टे, आतंकवादी घटनाओं आदि के धूम्र आवरण में जनता और मीडिया का ध्यान उलझा रहे और ये गिद्ध कांग्रेसी डकैत अपनी कमाई के लिये षडयंत्रों के माध्यम से मोटा धन भी हजम करते रहे और उन्हें कोई देख भी न सकें।

इसी चींटाबर के चेले चपाटी जालसाजों दक्षिण भारतीयों की सैकड़ों माइक्रो फाइनेंस कं. हर शहर की छोटी बस्तियों में चलाई जा रही है। जो महिलाओं को 30%-42% की ब्याज दरों पर रु. 10,000/- से रु. 1 लाख तक वित्तीय सुविधायें उपलब्ध करवाकर काले धन को सफेद करने में लगी हैं। इंदौर की हर छोटी बस्ती में कं. के एजेन्ट आकर महिलाओं को उसी गली-मोहल्ले की औरतों का समूह बनाकर रु. 10,000/- प्रति माह रु. 250 की किस्त पर वर्षभर के लिये उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे ही जालसाज ऋणदाताओं का गिरोह 25 से 40% की ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने वालों का गिरोह हर शासकीय, निजी कार्यालयों, फैक्ट्रियों के आसपास भी वेतन मिलने के समय मंडराया करता है। बाद में भारी भरकम ब्याज दरों के चलते जब कोई ऋणी उनके 25 से 40% का ब्याज व मूलधन नहीं चुका पाता हैं, तो उसकी न केवल चल-अचल संपत्तियां वरन् बीवी, बेटी, बहुओं व घर की अन्य महिलाओं का खुलकर यौन शोषण करता हैं वरन् उन्हें आत्महत्या तक के लिये विवश भी कर देता है। जिसकी आये दिन अखबारों में खबरें पढ़ने को मिल जाती है। ऐसे 90% कं. ऋणदाताओं का कोई वैधानिक आस्तित्व न होने के कारण इस लूट के और अवैध वसूली के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी नहीं हो पाती, संबंधित थाना क्षेत्रों पर पैसा बंटने के कारण उल्टे ही पुलिस ऐसे ऋणीयों पर भी धन लौटाने का दबाव बनाती है। इन सारे कुकृत्यों और भारी भरकम ब्याज वसूली के शिकायतों को थाने से लेकर रिजर्व बैंक तक लोग पहुंचाते हैं परन्तु वसूली के चलते कार्यवाही भी मुश्किल से हो पात है। सबको संरक्षण भी वित्त मंत्रालय के ढीले कानूनों से ही मिलता है।

मीडिया के मक्कार, धूर्तों का सवाल है तो अब मीडिया तो वैसे भी माफियाओं के चंगुल में है। जिनका मूल उद्देश्य जन कल्याण न होकर दबाव और दहशत बनाकर वसूली करना ही है। वर्तमान में भी मीडिया के धूर्त सत्ता की रखैल बन जनता को ही रु. के अवमूल्यन के लिये दोषी ठहरा रहे हैं। जबकि यथार्थ में रु. की गिरती कीमतों में कालेधन और शासन में बैठे धूर्तों का ही सारा खेल हैं। जो सत्ता को बाप की जागीर समझ रिजर्व बैंक से लेकर सभी सरकारी बैंकों को अपनी तरह से चलाकर रु. की कीमतें गिरवाकर लाभ कमाने में लगे हैं।

### आईएएस इंडियन एक्यूसिंग सर्विस शाख के उल्लू जहां बैठे हैं- तबाही मचा देते है

# विद्युत वितरण कंपनी- चारों तरफ लूट, वसूली, भ्रष्टाचार

### प्र.स. से मीटर रीडर तक सब उपभोक्ताओं का कर रहे शोषण

विश्व व्यापार संगठन के पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनी का उद्देश्य ही था कि विश्व के सभी मोटी कमाई वाले संसाधनों पर हर देश में कब्जा करों। उसके लिये पहले उन राष्ट्रों के सत्ताधीशों को मोटी रकम देकर खरीदा फिर शोषणकारी कानून बनवाओं। राष्ट्रीय संपत्तियों, संसाधनों, उपक्रमों में विकास के नाम पर पहले ऋण बाटो, उनसे भ्रष्टाचार फैलाओं, रकम डुबने पर कर्ज वसूली के लिये दबाव बनाकर शर्ते मनवाओ। सबसे भ्रष्ट अधिकारियों को उनका मुखिया बनवाओ। व्यावसायिक कानून स्वरूप बनाओ। छोटी-छोटी कंपनियां बनवाओ, उन कंपनियों में खुलकर जालसाजियां करवाओ। एक तरफ जनता को लूटो, दूसरी तरफ इसके लिये घाटा दिखाओ और हर सरकारी सेवाओं, संसाधनों की कीमतें बढ़वाओ। इस पूर्व नियोजित षड़यंत्रों का अंजाम वर्तमान में जनता के सामने है। इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है- राष्ट्र के सभी राज्यों के लाभ चलते हुए सारे राज्य विद्युत मंडलों को खंड-2 पहले सरकारी कंपनियों में बांटा गया, बांटने के पूर्व केन्द्र सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के दबाव में विद्युत मंडल के कानूनों में भारी फेरबदल कर उपभोक्ताओं के शोषण के लिये विद्युत देयक जमा न करने, चोरी करते पाये जाने व अन्य मामलों में सीधे जेल भेजने की व्यवस्था तो कर ही दी इसके विपरित कं. उनके प्रबंध संचालकों से लेकर लाइनमेन, मीटर रीडरों तक की सुरक्षा के पूर्ण उपाय किये परंतु इनकी वसूली, गलत रीडिंग करने, रीडिंग न करने, विद्युत मीटरों की कई गुना ज्यादा तेज गति से चलने, उचित रीडिंग न करने, विद्युत आपूर्ति न होने से उपभोक्ताओं को होने वाली क्षति, विद्युत कं. के कर्मचारियों के अधिकारियों की लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं व उसकी क्षति पूर्ति जानबूझ कर अधिकारियों द्वारा लाइनों, ट्रांसफार्मरों के रख-रखाव न करने से होने वाली जनता की परेशानीयों के बारे में ठोस कानूनों की जानबूझकर व्यवस्था नहीं की गई, साथ ही इन कं. के अधिकारियों, इंजिनियरों की कारगुजारियों,उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनने, मीटरों के निर्धारित मापदंडों, तेज गति से चलने आदि के बारे में भी कोई स्वतंत्र जांच, न्यायिक एजेन्सी न तो सरकारी स्तर पर न ही कोई अशासकीय स्तर की संस्थाओं की व्यवस्था की गई जो इन हरामखोर भ्रष्ट जालसाज कं. के प्र.स., अभियंताओं, यंत्रियों से लेकर शिकायत केन्द्रो, लाइनमेन, मीटर रीडिरों के लूट, वसूली,अवैध कारोबार से लेकर उपभोक्ताओं के घरो की महिलाओं के यौन शोषण के विरुद्ध कार्यवाही ठोस तरीके से कर इन्हें सजा दिलवा सके और जो व्यवस्थाएं इस कानून में की गई उसके अंतर्गत 10-25 लोगों का जो विद्युत नियामक आयेग बनाया भी गया तो उसमें भी जालसाजी पूर्ण तरीके से उन भ्रष्ट घूर्त आई.ए.एस. जो प्रशासनिक सेवा से सेवा निवृत हो चुके थे, उन मुखेरों को ही आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, जिन्होंने जिंदगी भर प्रशासन कमें अजगर की भांति चिपक कर जहां पर भेजे गये बिना डकार लिये निगला और हजम कर गये, अब जब से मुख्य सचिव से सेवा निवृत्त होकर मप्र विद्युत नियामक आयोग में अध्यक्ष बना बैठाये गये राकेश साहनी आय के योग बने रहे ये देख रहा है, जो मुखेरा श्वान आय के योग देख रहा हो उसे क्या मतलब

कि इन विद्युत वितरण उत्पादन और प्रारक्षण कं. में कैसे हजारों करोड़ डकार कर पूरी प्रणाली को नष्ट किया जा रहा है। उल्टे वो वर्ष में दो बार आंख भींचकर विद्युत की दरें बढ़ाता जा रहा है। वहीं विद्युत उत्पादन कं. के भी घूर्त आई.ए.एस. बनाम इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के ये अधिकारी पुराने प्लांटों को कभी कोयले की कमी बताकर, कभी प्लांटों को पुराना बताकर तो आज भगड़िया डकैत प्रधान सचिव सुलेमान निजी टाटा, रिलायंस, हिंडालको जैसी कं. से अरबों रुपए प्रतिमाह की बिजली खरीदी कर रहा है और प्लांटों को जो मंडल के थे सारणी वीर, सिंगपुर में चल रहे थे बंद करवाकर जानबूझकर विद्युत की कमी निर्मित कर रहा है, ताकि 50 पै. युनिट की ताप विद्युत को रु. 4 से 5 रु. में खरीदी का बहाना बनाकर हर माह अरबों कमीशन मिल सके, दूसरी विद्युत की कीमतें बढ़ाकर आसानी से उपभोक्ताओं से भी कीमतें बढ़ाकर वसूली की जा सके।

विद्युत वितरण में भी हर कार्य में मोटा धन ऐंठने के लिये हर कार्य यहां तक कि बिलों की वसूली भी अपने ही वहां वर्षों से बैठे भ्रष्ट इंजीनियरों और सत्ताधीश नेताओं ने अपने ही रिश्तेदारों की फर्मों को सौंप रखी है। वर्तमान स्थिति यह है इस पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं. के मुख्यालय पोलोग्राउंड स्थित बिल संग्रहण केन्द्रों में भी ठेकेदार संस्था ने 5 खिड़कियों पर भी मात्र तीन ही कर्मचारी बैठाये है। यही हाल पूरे इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच के साथ प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों से लेकर ग्रामीण केन्द्रों का भी है। यही हाल बिजली सुधारने वाली टीमों का है। वे भी सब इंजिनियरों, नेताओं की ठेकों की कंपनियों का है। जो सुबह नो बजे से शाम 7 बज तक ही काम करते है। जहां पहले स्थायी कर्मचारी हुआ करते थे, अब तक पर भी ठेकों में काम दे दिया गया है। मीटर रीडिंग का भी अधिकतर कार्य ठेकों पर चल रहा है। इंदौर की इलेक्ट्रानिक्स कॉम्पलेक्स में कई कर्मचारी जिसमें एक 30वर्ष से जमा नि.श्रे.वि. गजेन्द्र चौहान है। इसका एक जीजा नरेन्द्र भदौरिया फर्शी वाली गली भागीरथपुरा में रहता है। जिसके संयुक्त परिवार का सारा भोजन, घरेलु कार्य तक हीटर पर किये जा रहे है। परंतु अनेकों शिकायतों के बाद भी पकड़ा नहीं गया। सारी बिजली चोरी की जलाई जा रही है। दूसरी और इसी वितरण केन्द्र में बैठा मीटर रीडर नीतेश म्हात्रे जो वर्षों से एक ही स्थान पर जमा है। मीटर रीडिंग मे बिल कम करने, कम रीडिंग लिखने, मीटर धीमा करने,बंद करने की महीना वसूली तो करता है साथ ही गरीब महिलाओं का यौन शौषण कर उन्हें खूली छूट देकर हीटर जलाने पर भी रु. 100-150 की ही प्रतिमाह बिल बनता है। जानबूझकर मीटर रीडर घरेलु मीटरों की रीडिंग करने दोपहर 12 से 4 के बीच जिन घरों में महिलाओं के अतिरिक्त कोई नहीं होता रीडिंग करने के बहाने, बातचीत करने पर घर की महिलाओं ज्यादा बिल आने की शिकायत करती है तो सीधा उनका उद्देश्य यौनाचार के लिये तैयार होने पर रीडिंग भी कम की जाती है और मीटर भी धीमा कर दिया जाता है और जो महिला इसके लिये तैयार नहीं होती उसे जानबूझ कर भारी भरकम बिल देकर परेशान किया जाता है। इस प्रकार ये हरामखोर जालसाज मीटर रीडर्स आराम से सैकड़ों महिलाओं का यौन शोषण भी करते है और उपभोक्ताओं से लाखों रु. प्रति माह की वसूली नियमित रूप से कर यथार्थ में बिजली कं. को करोड़ों का चूना लगाते रहते है। इसका दुष्परिणाम उन आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ता है जो ईमानदारी से बिजली का बिल जमा करते है। मीटर रीडरों का ये कड़वा सच न केवल फर्शी वाली गली भागीरथपुरा का ही नहीं हर शहर गांव के गली-मोहल्लों का पूरे प्रदेश और देश का है। उपयंत्री, सहा. यंत्री, का. यं., अयं. से मुख्य अभियंता से लेकर प्रबंध संचालकों को भी मालूम है। पर वितरण केन्द्रों पर उनके वरिष्ठों को उनका हिस्सा मिलता रहता है। दूसरी और आखिर इन मीटर रीडरों का हर छह माह में दूसरे वितरण केन्द्रों और तीन वर्ष में300 से 500 किमी दूर स्थानांतरण होते रहने से ये नौबत नहीं आये पर जब मीटर रीडर औश्र लाइनमेन से लेकर उपयंत्री, एमडी तक का उद्देश्य अपनी लूट और वसूली जनता को शोषित करते हुए घाटा ही दिखाना हो ताकि कीमतें लागत से 5 से 10 गुना बढ़ाकर वसूली करना हो तो फिर हर कर्मचारी को लूट की हर तरह से छूट देना जरूरी है। दूसरी और अभी तो ये कं. फिर भी सरकारी है। तब तक फिर भी जनता की आवाज कहीं न कही सुन ली जाती है। जबकि पूरी तैयारी है कि इसे पूर्णतः निजी हाथों में सौंप दिया जावे तब तो हालात और विकराल स्थिति में होंगे। तब न तो पूरी विद्युत आपूर्ति मिलेगी फिर भी बिल कई गुना के साथ ही आत्याधिक अनाप-शनाप होंगे। जब उपभोक्ता शिकायत करने पहुंचेगा तो यहां भी बिजली कं. के गुंडे और बाउंसर्स ने केवल उपभोक्ताओं की वरन अच्छे-अच्छे अधिकारियों और नेताओं तक की शॉपिंग मॉल्स की तरह पिटाई भी करेंगे और चूंकि पुलिस अर्थात सरकारी गुंडे महीना खाकर उन्हीं शिकायतकर्ता को ही मारेंगे, पीटेंगे और न्यायालयीन प्रकरण भी लादेंगे। वैसे वर्तमान में भी न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में वरन शहरीय क्षेत्रों में भी यह गुंडागर्दी न केवल इंदौर, भोपाल से लेकर पूरे प्रदेश के 50 जिलों और पूरे देश में इन विद्युत कं. की पिछले 10 वर्षों से ज्यादा समय से कं. बनने के बाद शुरू हो चुकी है। प्रदेशभर में लाखों मुकदमें इन बिजली कं. में अंट-शंट बिजली के बिल भेजकर नहीं जमा करने पर जेल भिजवाये कर लाद रखे है। आखिर इन कं. में बैठाये गये घूर्त आई.ए.एस. अधिकारी हजारों करोड़ रु. साल की लूट और भ्रष्टाचार से कैसे हजम कर पा रहे है। जबकि मंडल द्वारा बिछाई गई लाइनों के खंभों पर वर्षो से पुताई नहीं की जाने के कारण न केवल निम्न दाब की लाइनों बल्कि उच्च दाब की लाइनें उसके टावर्स 33,66,232 केबी के सब स्टेशनों, ट्रांसफार्मस के रखरखाव केवल कागजों पर ही कि जाकर सारा पैसा उपयंत्री, सहा. यंत्री, सभा. यंत्री से लेकर प्र.स. तक हजम कर रहे है। यहां तक कि धरमपुरी, सांवेर, देपालपुर से मिली जानकारी के अनुसार ये कर्मचारियों को दी जाने वाली बरसाती, गमबूट, ग्लब्ज, हेलमेट आदि जो फील्ड साफ लाइनमेन आदि को दी जानी चाहिये, उस तक का सारा माल ये उपयंत्री और सहा. यंत्री अगर खरीद भी लेते है तो अपने वालों को बांटकर दूसरे कर्मचारियों को देने की अपेक्षा बाजार में बैचकर खाने की शिकायते है। अराजकता की इस स्थिति में यदि उपभोक्ता वितरण केन्द्रों को घेरकर तोड़-फोड़ कर आग लगा देते है। स्वाभाविक है कि पैसा देने के बाद भी यदि जनता को परेशानियां उठानी पड़ती है तो कब तक बेहतर यह होगा कि इन कं. को समाप्त कर पुनः मंडल बनाया जाये। सभी निजी कं. को ठेकेदारी पर काम देना बंद कर स्थायी कर्मचारी नियुक्त किये जावे। बिजली बंद होने पर 24 घंटे वे कर्मचारी जनता को सेवायें दें, इन महा मक्कार साख के उल्लू रूपी आई.ए.एस. अधिकारियों के चंगुल से इस विद्युत को बचाया जाये। मंडल के अध्यक्ष के रूप में अभियंताओं को बैठाया जाये। भ्रष्ट इंजिनियरों, कर्मचारियों, मीटर रीडरों तक का हर वर्ग स्थानांतरण किया जाये। इलेक्ट्रानिक मीटरों के स्थान पर यांत्रिक मीटर लगाये जाये जो सही रीडिंग दर्शाये, चारों तरफ लूट-खसोट की मानसिकता पर शीघ्र अंकुश लगाया जाये अन्यथा परिणाम घातक होंगे।

### चुनावीकर्षण- अ (भी) टल ज्योति आगे-आगे पाठ, पीछे-पीछे सपाट

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 7-8 वर्षों में जालसाजियों, वसूली और जनता में छवी बनाने रखने प्रसार् माध्यमों में छाये रहने की कला में काफी मंज चुके है। शक्ल से, नाम शिव की तरह भले ही भोले दिखते हैं पर चेहरे के पीछे जालसाजी, भ्रष्टाचार के साथ ही डरपोक होना भी साफ झलकता है। जिस अटल ज्योति अभियान की 20 से अधिक क्षेत्रों में, जनधन बर्बाद कर 24 घंटे विद्युत आपूर्ति का वादा किया, समारोह, समाप्त होने के चंद घंटो बाद ही न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में वरन शहरीय क्षेत्रों में भी अंधकार का साम्राज्य छा गया। फिर उदघाटन वाले क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के लिये आजू-बाजू वाले जिला मुख्यालयों से लेकर गांवों तक की आपूर्ति कर कार्यक्रम की नौटंकी की गई। इस अभियान की नौटंकी का उजाला जब कुछ घंटों में ही अंधेरे में बदला,ये सिद्ध कर दिया कि यह चुनावीकर्षण था जबकि यथार्थ यही है कि चुनावीकर्षण में जनता को रिझाने केलिये निजी कं. यथा टाटा, रिलायंस से महंगी विद्युत खरीदकर यह नौटंकी की जा रही है और बरसात में घरेलु, व्यावसायिक और कृषि में विद्युत की मांग अत्याधिक कम होती है इसलिए आसानी से जहां अटल बनाम अ(भी)टल ज्योति की उस विशेष क्षेत्र में कुछ समय के लिये 24 घंटे आपूर्ति की जा रही है।

नवम्बर 13 में चुनाव के बाद फिर वही आधे रात-दिन अंधेरा होगा, चुनाव में भाजपा जीते या कांग्रेस मार्च के बाद से जो हजारों करोड़ रु. का एडीबी से फीडर सेंचरेशन का ऋण इसलिये ही लिया गया कि लाखों करोड़ की विद्युत लाइनों संपत्तियों को फीडर के अनुसार ठेकेदारों को सौंपकर चारों तरफ अंधेरा हो या विद्युत मिले न मिले जनता को नोंचने के लिये छोड़ दिया जाये।

साप्ताहिक समय माया

### मप्र लोक भ्रष्टाचार निर्माण विभाग लूट सके तो लूट

# मु.अ. काला, कमाई के लिये भ्रष्टों को दे रहे संरक्षण

## 11 कार्य.यंत्री से कमीशन, महीना वसूली के हेतु दे रहे लूटकी पूरी छूट

**इंदौर।** पश्चिमी अंचल के लोक निर्माण विभाग यथार्थ में भ्रष्टाचार निर्माण विभाग है, जिसके भ्रष्टाचार, लूट, जालसाजीयों के बारे में आये दिन समाचार पत्रों वृहद स्तर पर न केवल इंदौर वरन् पूरे प्रदेश में समाचार प्रकाशित होते ही रहते है, पर इन भ्रष्ट हरामखोरों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। शिकायतें करने पर ऐसी ढेरों शिकायतें हर दिन कचरे की टोकरी में डाल दी जाती है, क्योंकि जिसकी शिकायत जिससे की जा रही है, वो उससे महीना ले रहा हैं, जब महीना ले रहा है तो भ्रष्टाचार से ही तो आया है, स्वभाविक है भ्रष्ट को बचाना इनकी नैतिक जिम्मेदारी है।

यही कारण है कि सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर ये सारे जालसाज भ्रष्ट इंजिनियर हर कदम चालाकियों से आवेदक को हतोसित करने का अंतिम स्तर तक प्रयास करते है। कोशिश रहती है जानकारी देने की अपेक्षा आवेदक को अपील की जावे और अपीलेट अधिकारी अपने कनिष्ठ के विरूद्ध अपील येन-केन प्रकरण खारिज कर दे ताकि वह आयोग में जावे और ये तीन-चार वर्ष के लिये बच जाये और आवेदक परेशान होकर जानकारी मांगना छोड़ दे, बाद में अगर सूचना आयोग ने मुफ्त में देने के आदेश भी कर दिये तो भी मामला निरर्थक हो जाता है, मुख्यालय में पूरे मप्र लोक निर्माण विभाग का यह हाल पूरे मप्र में है। प्रमुख अभियंता अग्रवाल भी दोनों हाथ से धन बंटोरने में लगा है और लगभग रु. 50 से 80 करोड हर महीने आवंटन देने, स्वीकृतियों, ठेकेदारों के पंजीयन आदि में वसूली करता है। वर्षों बाद बड़ी मुश्किल से मुख्य अभियंता कार्यालय से तीन-चार माह बाद जानकारियां जो प्राप्त हुई जो स्पष्ट करती है कि किस प्रकार मुख्य अभियंता के अंतगर्त 11 संभागों में लूट-पाट और भ्रष्टाचार चल रहा है।

सं.क. 1 में रा.रा. कं. 3 एबी रोड का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण करने के लिये 15.50 किमी के अनु.क्रं. 228/05-06 में स्वीकृत किया गया था। आईटीएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रालि को जिसकी लागत रु. 5 करोड 26 लाख 58 हजार में स्वीकृत दर से 5.48 प्रतिशत अधिक एसओआर पर किया गया था। जो 10 माह में किया जाना था। कारण बताया गया बिजली के खंभे एवं पेड़ नहीं हटाये गये, साथ ही मु.का.अ. इंदौर विप्रा ने पत्र क्रं. 5682 दि. 03.08.07 द्वारा निर्देशित किया कि सड़क पर बीआरटीएस कॉरिडोर बनाया जाना है, इसलिये कोई काम नहीं किया जाये इसलिये क्रं. ने कोई कार्य नहीं किया। इस अनु.को को का.यं.स.क. ने अनु. की धारा 14 में पत्र क्रं. 438/09 दिनांक 15/11/2010 को समाप्त कर दिया था जबकि भुगतान इन जालसाजों ने सन 2010 तक लगातार किये जाते रहे, अर्थात सारी झूठी एमबी भरी जाती रही और बचने के लिये पत्राचार जाते रहे। इनती सारी जालसाजियों को वैध करार दे दिया। पत्र क्रं. 980 दिनांक 14/2/12 से उसके दंड राशि भी नहीं काटी गई। इस रु. 5.50 करोड़ से ज्यादा की बंदरबांट में केवल बहाने और कागजी कार्यवाही की जाती रही और सारा पैसा मुख्य अभियंता काला के संरक्षण में का.यं., उपयंत्री, सहा. यं. ने मिलकर ठेकेदार आयटीएस के साथ हजम कर लिया गया। सं.क. 1 के अंतगर्त मांगलिया तिराहे से रिंग रोड तक 6 लेन रोड बनने में भी 3 विस्तार दिया जा रहा है। बाने वही खंभे शिफ्ट नहीं हुये अतिक्रमणकारी हो उसकी आड़ में जो महंगाई वृद्धि लाभ दिया जायेगा।

कार्य विभागों में खरीदी में होन वाली लूट-पाट को रोकने के लिये खरीदी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा होने के बाद भी पूरे मप्र के सभी संभागों में खरीदी धड़ल्ले से जारी है। फिर रु. 25000/- से ज्यादा की खरीदी और रु. 2 लाख से ज्यादा के कार्यों में जिसमें निर्माण मरम्मत कार्य होना है उसके लिये निविदाये दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की जानी चाहिये, परंतु इसके विपरित बिना निविदा बुलवाये खरीदी की जा रही रही है। संक्र. 1 ने पत्र क्रं. 10/सामान्य/भंडार/11-12 इंदौर दिनांक 05/01/12 50 नग स्प्रिंग पोस्ट खरीदे। उक्त पत्र से मु.अ.कार्या ने स्वीकृति दी। रु. 2 लाख के मु.अ.का. के पत्र क्रं. 91 दिनांक 5/1/12 से क्रं. 1, इंदौर को रु. 5 लाख के क्रय की अनुमति दी गई जिसमें 10 रेट्रो रिफ्लेटिन साइन बोर्ड, विलेज बोर्ड 2 नग, 12 जंक्शन बोर्ड, 80 नग स्पीड बॅम्प्स खरीदे गये। खंडवा संभाग को रु.197098 रुपए की विक्रय गृह के सामान खरीदने की स्वीकृति दी गई। संभाग क्रं. 2, इंदौर 28 नग ग्रामीण साइन बोर्ड और 60 नग प्लास्टिक स्पीड ब्रेकर खरीदने की रु. 2.15 लाख की पत्र क्रं. 268 इंदौर दिनांक 10/01/12 को दी गई फिर पत्र क्रं. 224 दिनांक 10/01/12 से 464 नग स्पीड ब्रोकर, 4 साइन बोर्ड रु. 6 लाख भेजी गई। अलीराजपुर संभाग को 269 दिनांक 10/01/12 को साइन बोर्ड खरीदने की रु. 6,64,000/- की दी गई। का.य. झाबुआ को आदेश क्रमांक 337 दिनांक 13/01/12 से 288 प्लास्टिक गति अवरोधक 288 नग रु. 3,10,000 की का.यं. खंडवा को पत्र क्रं. 351 दिनांक 13/01/12 को 6 नग गति अवरोधक, 40 नग संकेत पटल के लिये रु. 4.30 लाख की पत्र क्रं. 352 दिनांक 13/01/12 से 100 नग गति अवरोधक, 32 नग जेब्रा साइन बोर्ड के लिये रु. 2.37 लाख की, पत्र क्रं. 350 दिनांक 13/01/12 से 20 नग जेब्रा साइन बार्ड रु. 85 हजार की, कां.य. (वि.यां.) इंदौर को इ.पी.ए.बी. सिस्टम के लिये रु. 5,28,700 की, पत्र क्रं. 336 दि. 13/01/12 से, का.य. झाबुआ को पत्र क्रं. 666 दि्र 31/01/12 से 260 ड्रम 80/100 ग्रेड डॉमर खरीदने की अनुमति दी गई। यह ड्रामर शासन के पैसों से खरीदकर छोटे-छोटे ठेकेदारों को देकर पेंच वर्क करवाया जाता है। ठेकेदार बिलों में डामर की राशि जोड़कर बिल भुगतान प्राप्त करता है। उसके भुगतान में से डामर की मत का.यं. वसूल कर हजम कर लेता है, यह सारी कई गुना ज्यादा कीमतों पर धन हजम करने की नियत से जन.12 में ही खरीदी गइ, जिसमें 50 प्रतिशत से ज्यादा की बंदरबांट हुई। का.यं. झाबुआ को को पत्र क्रं. 1415 दि. 17/04/12 से 54 नग रेट्रो रिफ्ले संकेत पटल 54 नग रु. 6.75 लाख की, का.यं. अलीराजपुर को पं.क्र. 2666 दि. 11.05.12 को 40 मी. टन डामर खरीदने धार को पत्र क्रं. 2841 से दि. 18.05.12 से 196मी टन डामर बड़वानी को पत्र क्रं. 2840 दि्र 18/05/12 से 200 नग ड्रम डामर, स.क्र. इंदौर को पत्र क्रं. 2839 इंदौर दि. 18.05.12 से, 300 ड्रम डॉमर, 100 ड्रम इमल्सन क्रम की, का.यं. खंडवा को पत्र क्रं. का2836 इंदौर दि. 18.05.12 से 200 ड्रम डॉमर व 120 ड्रम इमल्सन क्रय की, का.यं. खरगोन को पत्र क्रं. 2896 दि्र 23/05/12 से 126 नग साइन बोर्ड क्रय रु. 12.50 लाख का.यं. स. 1, इंदौर को पत्र क्रं. 3108 दि. 31/05/12 से सड़क सुरक्षा उपकरण क्रय हेतु रु. 20 लाख की, का.यं. से क्रं. 2 को पत्र क्रं. 3/23 दिनांक 01/06/12 से 100 मीट टन डॉमर, 50 मी इमल्सन क्रय की, का.यं. बि.यां. इंदौर को पत्र क्रं. 3666 दि. 19/06/12 को 4 नग टन स्पिलिट एसी रु. 1,81,060 प्रत्येक एसीएफ क्रय की प्रत्येक रु. 49,000 , का.यं. अलीराजपुर को पत्र क्रं. 385-2-53 दि. 26/06/12 से दो नग बेट्री, पत्र क्रं. 3641 दि. 26/06/12 से 12 में. टन इमल्सन पत्र क्रं. 3843-44 दिनांक 26/06/12 से 200 नग सीमेंट, क्रा.यं. झाबुआ को पत्र क्रं. 3906-07 दि. 29/06/12 से 300 ड्रम डामर, खरगोन को पत्र क्रं. 4085 दि. 03/07/12 से, 3 रेट्रो रिफ्लेक्टिव केन्टिलिवर साइन बोर्ड 3 नग रु. 3.36 लाख, प्रत्येक रु. 2,78,833/- रु. का, का.यं. अलीराजपुर को पत्र क्रं. 4309 दि. 13/07/12 से, 1 कम्प्यूटर, प्रिंटर आदि के लिये हरामखोरों ने इसमें कीमत नहीं दी। का.य. वि.यां. इंदौर को पत्र क्रं. 4430 दि. 19/07/12 से 8 नग 2 टन स्पिलिट एसी कीमत रु. 4,43,100/- प्रत्येक रु. 55387/- का, का.यां. खंडवा को पत्र क्रं. 4799 दि. 07/08/12 से 80 साइन बोर्ड के रु. 8.20 लाख की प्रत्येक रु. 11500/- पत्र क्रं. 4800 दि. 07/08/12 से 44 नग साइन बोर्ड रु. 5.326 लाख की औसत रु. 12105/- प्रति बोर्ड, जबकि बाढ़ के पानी के लिये सबसे बड़ा बोर्ड 3 फुट×4फुट का भी अधिकतम रु. 5000/- में लग जाता है। जिसके मात्र 12 नग ये.का. यं. झाबुआ को पत्र क्रं. 4337 दिनांक 17/08/12 से 100 नग साइन बोर्ड कीमत रु. 11 लाख अर्थात प्रति साइन बोर्ड रु. 11000/- जबकि 38 का आकार 4×3 है, जिसकी अधिकतम कीमत रु. 5000/- से ज्यादा नहीं, का.यं. खरगोन को 48 नग साइन बोर्ड रु. 6.20 लाख प्रत्येक की कीमत रु. 12916 से 12 टन डामर क्रय की, बड़वानी को विश्राम गृह के लिये पत्र क्रं. 5719 दि. 21/09/12 से रु. 6.96 लाख, कां.य. सं. क्रय इंदौर को 100 टन डॉमर की पत्र क्रं. 6174 दि. 6174 दि. 009/10/12 से, खरगोन को पत्र क्रं. 6176 दि. 04/10/12 से 260ड्रम डामर, झाबुआ को 2600 ली. पेंट रु. 2.25 लाखा, अलीराजपुर को पत्र क्रं. 6359 दि. 17/10/12 से 200 ड्रम डॉमर, 60 ड्रम इमल्सन, कां.य. यां. इंदौर को पत्र क्रं. 19/01/12 3 नग 2 टन एसी, युपीएस से मय बेट्री के (कीमत नहीं दी गई है, संभवतः रु. 3 लाख, धार को पत्र क्रं. 7702 दि्र 31/12/12 के.सं. नि. 1 कम्प्यूटर, 1 प्रिंटर क्रय की झाबुआ को 14 नग एसी रु. 4, 41, 000/- प्रत्येक रु. 31500 जबकि बाजार में कीमत रु. 20000/- के लगभग, पत्र क्रं. 428-30 से 12/1/13 को क्रय की अनुमति का.यं. बड़वानी को पत्र क्रं. 428 दि. 12-1-13 से रु. 2 लाख की विश्राम गृह के नाम पर खरीदी की अनुमति जिसमें डायनिंग टेबल, ग्लास टाप के साथ रु. 38000/- बड़वानी को पत्र क्रं. 427 दि. 12/01/13 से 475 ली. पेंट रु. 3.15 लाख अर्थात प्रति ली. 239/- प्रति लीटर की अनुमति दी गई। इस खरीदी से अंदाज लगाया जा सकता है कि इसमें कितना कीमशन, कितनी कम आपूर्ति की गई होगी, हरामखोरों और जालसाजों ने कई पत्रों में कीमत नहीं लिखी है। डामर की खरीद में इसमें भी लंबा खेल न केवल सभी कार्यपालप यंत्री वरन खंडवा अ.यं. पांचोली और इंदौर एसई जैसगार कर रहे है। अं.य. और मु.अ. को सारे कार्यपालन यंत्री तब ही महीना देते है जब उन्हें लूट की पूरी छूट मिलती है। यही कारण है कि सूचना के अधिकार में कोई जानकारी नहीं देना चाहता क्योंकि हर कार्य में हर कदम-कदम पर ये भारी, भ्रष्टाचार करते है। और ठेकेदारों के इशारों पर नाचकर उन्हें भ्रष्टाचार से लूट और कमाई के अवसर देकर अपना शेष हिस्सा डकार रहे है। तब ही तो विधायकों से लेकर अं.य., मु.अं., सचिव, प्र.स. मंत्री को हिस्सा पहुंचाते है।

हर समय वृद्धि, मूल्य वृद्धि में अनुबंध की समाप्ति में, अं.यं., मुं.अ. अपना हिस्सा डकारे बिना स्वीकृति नहीं दी जाती है, यही कारण है कि कभी भी कोई भी कार्य समयावधि में पूरा नहीं होता, सेतु में अनुबंध के समय दरों से कम पर काम लेने के पीछे कार्य को हथियाना और हथियाने के बाद लटकाना ये तुके का.यं. की परंपरा रही है।

पहले अंड़गे उलझाना, फिर कार्य लटकाना, तदुपरांत उसे समय वृद्धि, मूल्य वृद्धि स्वीकृत करना, फिर मूल कीमत डेढ़ से दो गुना तक भुगतान करवाना। उसमें से अपना हिस्सा हजम कर जाना, ऊपर से भ्रष्टों और जालसाज का इतिहास कां.य. रा.ना. मिश्रा को समाचार पत्रों में वर्षों से प्रकाशित होता रहा है, वैसे इससे धूर्त लो.नि.मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी इसका घोर विरोधी रहा,इसके विपरित पुनः इंदौर में आकर सेतु संभाग में फिर तांडव कर रहा है। यही हाल सभी कार्यपालन यंत्रियों का है, यथार्थ में लोक भ्रष्टाचार निर्माण विभाग है।

# स्पष्ट निर्देशों के बाद भी टेक्सियों का मनमाना भुगतान

**( पेज 2 का शेष )**

(1) वाहन किराये पर लेने की स्वीकृति पूर्वानुसार वित्त विभाग द्वारा दी जावेगी। वाहन किराये पर लेने की व्यवस्था संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा की जा सकेगी।

(2) वाह किराये पर लेने हेतु मासिक दरें नियमानुसार, सेवाकर (सर्विस टैक्स) हेतु पंजीकृत फर्मों/संस्थाओं से, निविदा आमंत्रित कर निर्धारित की जानी चाहिए। सेवाकर हेतु पंजीकरण न होने की दशा में यह सुनिश्चित किया जाये कि संबंधित संस्था/फर्म द्वारा टैक्सी सेवाओं का दिया जाना, प्रचलित नियमों में अनुमत्य है। किराये पर लिये जाने वाले वाहनों हेतु पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर निविदा के माध्यम से ही ऑफर्स प्राप्त किये जाने चाहिए।

(3) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड वाहन ही किराये पर लिए जाए।

(4) जिन अधिकारियों हेतु वाहन किराये पर लिये जा रहे हैं उन अधिकारियों के मूल पद के ग्रेड पे के आधार पर वाहन किराये पर लिये जाने हेतु निम्नानुसारा मापदण्ड निर्धारित किए जाते हैं-

रु. 5400 एवं रु. 6600 ग्रेड पे पाने वाले अधिकालियों के लिये वाहन की अधिकतम लागत सीमा रु. 3.5 लाख (एक्स शोरूम प्राइस) तक होगी।

रु. 7600 ग्रेड पे पाने वाले अधिकारियों के लिये वाहन की अधिकतम लागत सीमा रु. 4.25 लाख (एक्स शोरुम प्राइस) तक होगी।

रु. 8700 एवं रु. 8900 ग्रेड पे पाने वाले अधिकारियों के लिये वाहन की अधिकतम लागत सीमा रु. 6.50 लाख (एक्स शोरूम प्राइस) तक होगी।

रु. 10,000 ग्रेड पे पाने वाले एवं रु. 67,000-79,000 उच्च स्तरीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे अधिकारियों के लिये वाहन की अधिकतम लागत सीमा रु. 7.50 लाख (एक्स शोरूम कीमत) तक होगी।

(5) मासिक आधार पर वाहन किराये पर लिए जाने हेतु मुख्यालय पर अधिकतम 1000 किलोमीटर की सीमा को आधार माना जाए। इस हेतु प्रतिदिन किराये के वाहन की उपलब्धता हेतु समय भी निर्धारित किया जा सकता है, जो 12 घंटे से अधिक न हो। वाहन किराये के फिक्स्ड चार्जेज निर्धारित किए जाना चाहिए।

(6) किराये पर वाहन लेने हेतु निविदा आमंत्रण में मुख्यालय पर भ्रमण हेतु फिक्स्ड चार्ज तथा मुख्यालय से बाहर भ्रमण हेतु वेरिएवल चार्ज पृथक-पृथक प्राप्त करना चाहिए।

(7) सामान्यतः शासकीय कार्य से यात्रा करने पर लोक-वाहक से ही यात्रा की जाना चाहिए परंतु अपरिहार्य स्थिति में किराये की गाड़ी का उपयोग करने की स्थिति में इसका अनुमोदन नियंत्रण अधिकारी से होना अनिवार्य होगा। इस हेतु नियंत्रण अधिकारी को कारण सहित किराये की गाड़ी से मुख्यालय के बाहर यात्रा करने के आदेश जारी करने होंगे। ऐसी स्थिति में कंडिका 6 में दर्शाये अनुसार वेरियबल चार्ज अनुसार भुगतान किया जा सकेगा।

(8) प्राप्त निविदाओं का विश्लेषण एवं मूल्यांकन (एनालायसिस एण्ड इवोल्यूशन) फिक्सड चार्जेस, वेरिएबल चार्जेस, मुख्यालय के बाहर की यात्राओं हेतु अनुमानित निर्धारित औसत दूरी आदि कारकों (फैक्टर्स) के आधार पर किया जाये एवं तदनुसार सफल निविदाकारों को क्रमबद्ध किया जाए ताकि वाहनों की अधिप्राप्ति हेतु उपयुक्त एवं सही दरें निर्धारित हो सकें।

(9) उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर विभागाध्यक्ष द्वारा प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन कर उत्तरकारी निविदाओं (रिस्पांसीव टेंडर्स) को क्रम बद्ध कर संविदा प्रदाय हेतु सफल निविदाकार का चयन किया जाय।

(10) संविदा के कार्यान्वयन की अवधि में सेवा प्रदाता द्वारा संविदा का निष्पादन भली प्रकार किया जा रहा है इसका निरंतर परिवीक्षण (मॉनिटरिंग) भी विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जाये।

(11) यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। इस आदेश के जारी होने के पूर्व तत्समय जारी निर्देशों/शर्तों के अनुसार कार्यालयों द्वारा किराये पर लिये गये वाहनों के संबंध में पूर्व निर्देश/शर्तें ही संविदा अवधि समाप्त होने तक लागू रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

### म.प्र. खाद्य एवं औषधि विभाग पहले ही महाभ्रष्ट, ऊपर से सरकारी दबाव

# डकैतों और जालसाजों की सहकारिता- सांची और अमूल दूध घोर स्तरहीनता

**वर्षों से पूरे प्रदेश में नमूने नहीं लेने देते, अमूल में तारीख, बैच नं., उपयोगिता, अवधि तक नहीं**

म.प्र. स्वा. विभाग के अधीन कार्यरत म.प्र. खाद्य एवं औषधि विभाग को कम से कम म.प्र. में महत्वपूर्ण भूमिका, जनता की जिंदगी में अदा करने वाले इस विभाग को शासन के मुखिये मु.मं., स्वा. मंत्री, अन्य मंत्रियों ने घोर अपेक्षित बना रखा है, इस विभाग में न केवल अधिकांश स्थानों पर न तो अच्छे भवन, कार्यालय, संचार साधनों, वाहनों का तो अभाव है, ही साथ ही 50 जिलों में मात्र 40 औषधि निरीक्षक हैं, जबकि कम से कम 250 होने चाहिए, ये बेचारे 40 हरामखोर जालसाजों को महीना वसूली, औषधि अनुज्ञप्ति जारी करने, नवीनीकरण करने में ही पूरा समय व्यतीत हो जाता है, तो क्या ये पूरे म.प्र. के शहरों में 25000 से ज्यादा फुटकर दुकानों में, दुकानों की औषधियों की फैक्ट्रियों में, क्या वो नमूने लेंगे, क्या जांच करेंगे, तहसीलों में तो वर्षों से औषधि निरीक्षक वसूली करने भी वार्षिक नहीं पहुंच पाते, यही कारण है कि पूरे म.प्र. में 99% थोक और फुटकर औषधि विक्रेता स्तरहीन, समयबाधित, प्रतिबंधित दवायें भी धड़ल्ले से बेच रहे हैं। पर यहां तो अंधे पीसे कुत्ते खाये, इसलिये ये 40 औ.निरीक्षक भी मात्र वसूली करने और पुराने न्यायालयीन प्रकरण निपटाने में ही जिंदगी धन्य मानकर रु. 25-50/- प्रतिदिन अंदर करके इतिश्री कर लेते हैं अपने कर्त्तव्यों की, इसके मुख्यालय भोपाल में भी इस विभाग का प्रभार भी किसी धूर्त और भ्रष्ट इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारी के पास होता है वह टुकड़खोर भी टुकड़े पाकर बोटियां चूसते बैठा रहता हैं।

इसकी दूसरी शाखा है, खाद्य विभाग जिसमें अग. 2011 से खाद्य विभाग का पुराना खाद्य अपमिश्रण निवारण अधि.04 समाप्त कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि. 2006 लागू कर दिया गया है, जिसमें अभी तक 2 वर्ष बाद खाद्य सुरक्षा आयुक्त की अलग से नियुक्ति नहीं की जा सकी हैं, अभी खाद्य और औषधि प्रशासन नियंत्रक एक ही अधिकारी डीडी अग्रवाल वैद्य हैं, जिसके स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी ब्रांडेड कं. के नमूने न लिये जायें, अर्थात पूरे म.प्र. में आईटीसी, पारले, हिन्दुस्तान लीवर, केडबरिज, अमूल, हल्दीराम भुजियावाला, टाटा, रिलायंस फ्रेश जैसी अनेकों बहुराष्ट्रीय कं. अपने उत्पादों और उनकी बिक्री के अनुपात में इसे महीना बांटती हैं, इसलिये महीना देने वाली कं. के वफादार पालतू उनके टुकड़े खाकर कैसे उनके विरुद्ध कार्यवाही को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधि.06 यथार्थ में सोनिया और उसकी संप्रग गिरोह ने बनाया ही जनता को लूटने, स्तरहीन, मिलावटी, रसायनयुक्त माल से 100 गुना कीमत पर बेचकर खिलाने के लिये हैं, जिनसे केन्द्र में बैठी सरकार को मोटा अरबों रु. में कमीशन मिलता रहे, मासिक तौर पर इन बहुराष्ट्रीय कं. से, उनका माल बिके और देशी उद्योगों और विक्रेताओं का नष्ट कर दिया जायें, जिसके परिणाम बिल्कुल वैसे ही सामने आ रहे हैं। जैसा कि समयमाया ने सन् 2007, 08, 09, 10, 11, 12, 13 के समाचार पत्रों में लिखा था, जिसमें जनता के लिये न तो खाद्य की सुरक्षा है और न ही कोई मानक, उन्हें से पैकिंग के नाम पर रु. 5/- का 100 ग्राम आलू चिप्स रु. 25/- में 25 ग्राम बेचकर देश की जनता को लूटा ही जा रहा है। अर्थात रु.

1000/- प्रति कि. अ1 यदि रु. 100/- प्रति किलो आयुक्त, मंत्री, खाद्य विभाग को डाल भी दिया गया तो रु. 50/- के माल के रु. 900/- बटोरेंगे तो कैसे इनके नमूने लिये जा सकते है।

भारतीय जनता के बच्चे से लेकर बूढ़े तक को दिन भर में दूध के खाद्य पदार्थ के रूप में सेवन से लेकर चाय, कॉफी, आइसक्रीम, मिठाइयों तक में दूध की आवश्यकता पड़ती है, म.प्र. में दूध के संग्रहण विपणन के लिये उसकी सहकारी संस्थायें हर संभाग स्तर पर हैं। म.प्र. में सहकारिता चाहे शासन की संस्था हो या निजी स्तर पर- सहकार मिलकर करो भ्रष्टाचार, सदस्यों और हितार्थीयों का बंटाढार अर्थात मंत्री सभी क्षेत्रीय स्तर की संस्थाओं यथा ग्वालियर दुग्ध संघ, भोपाल दुग्ध संघ, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, सागर के दुग्ध संघों के अध्यक्ष से लेकर प्लांटों के प्रभारी, क्रय, विपणन, विक्रय अधिकारी, प्रबंध संचालक एक तो वर्षों से कुंडली मारे अत्यधिक लूटपाट और भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, स्वाभाविक है इसका सीधा असर घाटे को पूरा करने के लिये कीमतों और गुणवत्ता पर पड़ता है, दूसरी ओर जब दुधारु पशु गाय-भैंस ही आत्यधिक कम हैं, तो संग्रहण से 5 गुना ज्यादा दूध की बिक्री कैसे की जा रही हैं, जबकि पूर्ण क्रीम युद्ध दूध में 6 से 8% फेट के स्थान पर मात्र 1-2 % फेट भी नहीं होता है, रु. 6 व 13 की थैली में तो सप्रेटा के स्तर का भी दूध नहीं होता, फिर छाछ, लस्सी, दही, पेड़े, फ्लेवर्ड दूध की कहां से आ रही है, अधिकांश दूध जो पैक किया जा रहा है, पाउडर और रसायनों के साथ पैक किया जा रहा है, सारे विज्ञापन झूठे हैं। ताजे दूध और पौष्टिकता के नाम सबको लूट और भ्रष्टाचार से धन चाहिए।

यही हाल अमूल दूध का है, इसमें न तो पैकिंग की तारीख और न बैच नं. भी डाला जा रहा है, जिसके यहां से दूध पकड़ा जाये वही सब जिम्मेदार होते हैं। जबकि अमूल का दूध गुजरात से अलग है और पैकिंग देवास के प्रीमियर मिल प्राडक्ट्स में होती हैं, परन्तु देवास में बैठी महाभ्रष्ट खाद्य निरीक्षक पथरोल जिसे देवास 7-8 वर्ष हो चुके हैं महीना वसूली कर आंख मींच पैकेट को न केवल स्तरहीन वरन बिना तारीख और बैच नं. तक का दूध पैककर बिकवा रही है।

इन्हीं दोनों अमूल और सांची जिस पर जनता को मजबूरन विश्वास कर अत्यधिक कीमत देकर उपयोग करती है, के भ्रष्टाचार की कीमत चुकाना पड़ रही है। ये दोनों भारी हरामखोर जालसाज सहकारी संस्थायें अपनी स्तरहीनता जिसमें न तो लिखे अनुसार फेट और पौष्टिकता होती है, न ही शुद्धता सारे म.प्र. के हो या गुजरात के मंत्री से लेकर नीचे तक के अधिकारी भ्रष्टाचार से धन वसूलते हैं और घाटे पूरा करने के लिये हर वर्ष भरी बरसात में भी कीमतें बढ़ाकर न केवल स्वयं तो जनता को लूटते ही है, साथ में आम क्षेत्रीय दूध उत्पादकों को भी कीमतें बढ़ाने का मौका दे रहे हैं।

इन्हीं जालसाजों की लूट और भ्रष्टाचार ने मात्र 10 वर्षों में रु. 20 प्रति ली. दूध को रु. 40/- प्रति ली. करवा दिया। दूसरी तरफ इनकी दादागिरी और भ्रष्टाचार का सरकारी सहकारी संस्था होने के कारण पिछले 20 वर्षों से म.प्र. के खाद्य विभाग की किसी भी जिलों में बैठे खाद्य निरीक्षकों को एक भी नमूना नहीं लेने दिया गया है, अगर कोई नमूना लेने की कोशिश भी करता है तो हर जिलाधीश इन खाद्य निरीक्षकों को सीधा धमकाता है कि यहां नौकरी नहीं करना है, जब सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी गई तो मुख्यालय से स्पष्ट लिखा कि सांची के न केवल दूध वरन किसी भी उत्पाद का पिछले 20 वर्षों से कोई नमूना नहीं लिया गया यथार्थ में नमूना नहीं लेने दिया गया, जब विधानसभा में यही प्रश्न विधायकों के माध्यम से लगवाया गया तब विधानसभा में भी शासन ने स्वीकार किया के सांची के दूध व अन्य उत्पादों का पूरे म.प्र. में पिछले 20 वर्षों में कोई नमूना नहीं लिया गया, चूंकि सरकारी संस्था है, इसलिये खाद्य विभाग को न तो महीना देते हैं। नमूना देने के नाम पर धमकी। जब सरकारी संस्था स्तरहीन दूध, सवाई कीमत पर बिना मोटी भेंट चढ़ाये बेच सकती है तो बहुराष्ट्रीय कं. तो बाकायदा सारे सरकारी श्वानों को टुकड़ा डाल रही हैं, तो पाठक अंदाज लगा सकते हैं कि वो क्या नहीं कर रही होंगी, इसीलिए आयुक्त/नियंत्रक ने जिन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने ब्रांडेड के नमूने लिये, उनको 91 कारण बताओ नोटिस जारी कर अप्रत्यक्ष रूप से इन बहुराष्ट्रीय कं. की तरफ से कार्यालयीन स्तर पर धमका दिया, इस धमकाने वाली कार्यवाही के भविष्य में जन स्वास्थ्य पर भारी न केवल घातक प्रभाव पड़ेंगे साथ ही लूट भी सैकड़ों से हजारों गुना होगी। सूचना के अधिकार में इन नोटिस की प्रतियां मांगी गई तो एक तो समय सीमा में जवाब नहीं दिया गया।

दूसरी ओर अपील करने पर उस पर पत्र की प्रतियों के माध्यम से सारे जिलों को आवेदक को जवाब देने के लिये लिखा गया, जिलों के अधिकारियों द्वारा समय सीमा के बाद भी कुछ गिने चुनों ने जवाब दिये उसमें उन्होंने पैसे जमा करने के ही पत्र दिये। पूरे खाद्य व औषधि विभाग में कोई भी खाद्य सुरक्षा अधि. 5-7 वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं बचा है, सारी युवा फौज की काम से कोई मतलब नहीं, केवल वसूली और ऊपरी कमाई पर ही ध्यान केंद्रित रहता है, चूंकि जब इनका नियंत्रक ही दोनों हाथ वसूली में जुटा है, फिर स्थानांतरण टिके रहने मनचाही पदस्थापना सबके ही पैसे देना पड़ते हैं, तो भ्रष्टाचार और वसूली पर ही ध्यान केंद्रित करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं, बस केवल कागजी खानापूर्ति पूरी करते रहो।

हालात यहां तक है कि दूधियों ने अपने नमूने न लिये जायें, मनचाही कीमत पर दूध बेंच सके, इसलिए छावनी के भरत मथुरावाला जो भाजपाई नेता भी है, सारे निजी दूधियों को इकट्ठा कर रु. 500 से 2000/- तक की वसूली कर सब दूध वालों के खाद्य अनुज्ञाप्तियों की ठेकेदारी करना शुरू कर दी है, वो थोक के भाव में फार्म भरवाकर कुछ टुकड़ा इन सहा.खा.सु. अधि. या खाद्य निरीक्षकों को डालकर थोक भाव के अनुज्ञप्तियां जारी कर रहे हैं।

ये जनता के स्वास्थ्य की कीमत और विभाग की कार्यशैली दोनों के साथ खिलवाड़ है।

## लाखों करोड़ों डकारने के लिये हजारो करोड़ों का ऋण

पेज 1 का शेष

उन्हें विद्युत के बारे में अ,ब,स भी नहीं समझना था, किलो वॉट, एंपियर, यहां तक कि एक युनिट बिजली की खपत क्या होती है, घरेलु बिजली की दरे, व्यवसाय, औद्योगिक, कृषि आदि पर किस दर से शुल्क वसूला जाता है, यह भी नहीं जानते हैं तो बाकी विद्युत यांत्रिकीय के बारे में कुछ कहना सुनना तो मूर्खता है। अपनी कं प्रायोजक कं. को बैठाया जा सके, फिर प्रायोजक ऐसर अतिआवश्यक वस्तुओं सेवाओं मनचाही कीमत मनचाहे तरीकों से वसूलते हुए उस राष्ट्र, प्रदेश, नगर की जनता का मनचाहे तरीके चहूं दिशी, चहूं विधिशोषण कर सकें, जैसा कि विश्व के अनेकों राष्ट्रों में किया जा रहा है। पूरे राष्ट्र की हजारों वर्ष पूरानी सड़कों से लेकर वर्तमान में विकसित की जा रही सड़कोंजो राष्ट्र के जन-धन से बनाई गई थी, बनी बनाई हुई लाखों करोड़ की सड़कों पर हजारों करोड़ का ऋण लेने और विकास के नाम पर उन्हें ठेकेदारों के पास दुगुनी तिगुनी किमत में सौंपा जा रहा है, जबकि ठेकेदार उन्हें न्यूनतम कीमत पर विकसित कर टोल वसूली कर रहा है। ठेकेदार भी 5-10 प्रतिशत इन निगमों के इंजिनियरों से लेकर प्रबंध संचालकों को धन खिलाकर चौगुनी कीमत पर आसानी से 75 से 90 प्रतिशत बैंक से वित्त सुविधा प्राप्ती पर भ्झी राज्य सरकारे और केन्द्र सरकार एडीबी, वित्तीय संस्थाओं को गारंटी प्रदान करती है। अर्थात 25 करोड़ की वास्तविक पर रु. 80 से 90 करोड़ वित्तीय संस्थाओं के धन में से 5-10 करोड़ में काम करके वसूली शुरू कर दी तो भी उसने रु. 45 से 50 करोड़ हजम कर लिये। अगर ठेका अच्छा चला तो और न चला तो भी और किस्त जमा की तो नहीं की तो भी पैसा डूबने पर वित्तीय संस्थाये तो सरकार से जनधन की वसूली कर ही लेगी। उज्जैन-इंदौर 50 किमी मार्ग पर रु. 200 करोड की डीपीआर बनाई गई, रु. 20 करोड तात्कालीन एमडी सुलेमान ने हजम कर ली, ठेकेदार ने निर्माण में रु. 70-80 करोड खर्च कर भी दिये तो भी रु. 160 करोड में से उसने रु. 80 करोड़ की कमाई कर ही ली जो ऋण राशि थी अब मगर ठेकेदार कं, जानबूझकर खर्चे, वेतन, रखरखाव के चार गुना दिखाकर 3 गुना धन को सीधा झूठे वाऊचरों से सीधा अंदर कर ही रही है। बैंक की किश्तें नहीं भी जमा हो रही है तो सरकार भरेगी किस्ते उसकी, अर्थात ठेकेदार और निगमों के डकैतों की जो कमाई हो ही गई, अब चूंकि घाटा हो रहा है तो इसकी टोल दरें बढ़ाने का रास्ता है, कीमते बढ़ा कर उपभोक्ताओं को लूटो।

यही कहानी बिजली की की जनता भुगत रही है। सड़कों पर पूरे देश में शुरू हो ही गया है, अतः अति आवश्यक है जीवन के लिये जल। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियां अधिकांश राष्ट्रों में पहले मिनरल वॉटर, साफ्ट ड्रिंक के बहाने अतिविकसित और विकसित के साथ ही विकासशील राष्ट्रों में पानी पैक करके बेचना शुरू किया। जब बाजार तैयार हो गया तो फिर प्राकृतिक जल स्रोतों पर कब्जा करके पूरा पानी ऊंचे भावों पर बेचना शुरू कर दिया। जब जनता को यह समझ में आया तो मेक्सिकों में इन कं. को खदेड़ कर भगाया गया। इस राष्ट्र में भी वही कहानी दोहराई गई, पहले विकास के नाम पर ऋण दो, अधिकारियें और प्रशासकों को धन बांटो और स्त्रोतों पर कब्जा करों फिर दस से सौ गुना लाभ प्राप्त करने के लिये जनता का हर कदम शोषण करों।अब भारत में भी यही कहानी दोहराने के लिये, प्राकृतिक जल स्त्रोतों पर हजारों गुना कमाई करने के लिये, पहले नगर निगम को सीतरे जलास द्वितीय चरण, तृतीय चरण नर्मदा जल के लिये कर्जा बांटा गया,यह हाल पूरे प्रदेश के हर नगर में जलापूर्ति और निकासी के नाम पर बांटने के बाद यहीं कहानी पूरे देश के हरे शहर की है, लाखों करोड़ ऋण बांटने के साथ ही हर प्रदेश में जल निगम बना दिये गये है। अभी प्रादेशिक स्तर के ये निगम फिर नगर स्तर पर आयेंगे फिर बिजली की तरह हर नगर में जल आपूर्ति हेतु अलग कंपनियां बना दी जाएंगी। इसलिए विश्व बैंक, एशियन बैंक रु. हजारों करोड का ऋण देकर, लाखों करोड़ की संपत्तियां भविष्य में अपनी प्रायोजक कं. कमाई के उद्देश्य ही बांटती है और हमारे भ्रष्ट धूर्त मंत्री, भ्रष्ट प्रशासनिक सेवक 10-20 प्रतिशत कमीशन हजम करने के लियें आंख भींचकर उनकी सारी शर्तों पर यह सोचकर हस्ताक्षर करते चलते है, अभी तो धन कमाओं, भुगतान तो आने वाला करेगा, गुलाम तो तन-मन-धन से करेगा ही, स्वाभिमान तो हमारे पूर्वजों ने सहस्त्रों वर्ष पहले ही बैच दिया था।जनता ने इस देश की सत्ता जिसे भला मानव मान कर सौंपी वह ही दानव बन अपने पोषण के लिये उसी जनता का शोषण करने लगा। रू. 20 के पेट्रोल के अस्सी वसूलने पर भी सड़के मुफ्त नहीं। हमारी धरती पर हमारे पानी से बनाई 25 के. युनिट की बिजली के रु.5 घरेलु के, रु. 15 व्यवसायिक के वसूलने के बाद भी, न तो 24 घंटे बिजली ऊपर से हजारों करोड़ रु. घाप दिखाकर, भरपाई के लिये हजारों करोड़ ऋण लेकर भी निजी क्षेत्र में सौंपकर घोर लूट-मार और शोषण करने की नियत से तत्काल तो लाभ उठा लें, पर भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को जो भुगतना पड़ेगा वह तो ठीक, फिर इन सत्ताधीशों की क्या औकात हो जायेगी इसकी कल्पना से बेहतर वास्तविकता उन्हीं युरोपियन राष्ट्रों की वर्तमान गंभीर आर्थिक परेशानियों, बेरोजगारी से लगाई जा सकती है, पर इन कांग्रेसी धूर्त सत्ताधीशों को आजादी 40 वर्ष भी हजम न हो सकी और गुलामी वापस बुलाने के लिये ईस्ट इंडिया कं. की तरह बिट्रीश के नये संस्करण इंडियन पेने को कं., हिन्दुस्तान लीवर जैसी कं. के ईशारे पर 1985 के बाद से ही नाचने लगे थे। विश्व बैंक, एशियन बैंक, अंतराष्ट्रीय मुद्राकोष आदि से ऋण स्वीकारने का सीधा मतलब था सीधा गुलामी का आव्हान।

साप्ताहिक समय माया

## सोशल साइट्स- सोशल जासूसी

# गूगल, फेसबुक, ट्वीट्र-पूंजीपतियों, सत्ताधीशों की कठपुतली

## आमजन का शोषण, धन व समय की बर्बादी, विद्यार्थियों की बर्बादी

पूरेविश्व में आधुनिक तकनीकी और संचार साधन, इंटरनेट यदि संचार के तीव्रतम माध्यम हैं, तो शिक्षित युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक की बर्बादी का कारण भी बन रहे हैं। जिसके समाचार आये दिन पूरे विश्व के समाचार पत्रों और दृश्य दूरदर्शनीय श्रृंखलाओं पर देखने और पढ़ने को मिल ही रहे हैं। जिसमें किसी लड़की ने फेसबुक से लड़के से दोस्ती की लड़के की सारी जानकारी झूठी थी, वो शादी करने घर पहुंची तो दो बच्चे घर खेल रहे थे, बीवी को जानकारी लगी उसने लड़की और पति दोनों की पिटाई कर दी, फेसबुक पर ऐसे लाखों प्रकरण देखने को मिलते हैं। दुनियाभर में फेसबुक के कारण लाखों तलाक के प्रकरण अदालतों में पहुंच रहे हैं। जिसके पीछे फेसबुक के कार्यकर्ताओं का हाथ होता है, जिनका उद्देश्य केवल अपने व्यवसाय को बढ़ाने और कमाई करने की ओर होता है।

फेसबुक ट्वीटर, गूगल पर खाते खोलते समय आपसे सारी जानकारी मांगी जाती है, जिससे आपके रुझान, आपके कार्य, व्यवसाय, उम्र, शिक्षा और पते की जानकारी मांगी जाती हैं, जब आप विचार प्रगट करते हैं तो स्वस्फूर्त आपसे सहमत, आपसे मिलती जुलती प्रोफाइल के व्यक्तियों की जानकारी परस्पर विनिमय करने लगते हैं। आप अगर साधारण हैं, तो आपके लिये ढेर सारी सीमायें बना दी जाती हैं। आपके सरकार से संबंधित कोई यथार्थ और नकारात्मक टिप्पणी की होती हैं, तो उसे अपलोड ही नहीं किया जाता था उसे उड़ा दिया जाता हैं, यौनाचार जो सदाबहार, सर्वप्रिय से संबंधित विषयों की महिलाओं की टिप्पणियों, विचारों को, मुक्तापूर्ण नग्न चित्रावली जानबूझकर आपके पृष्ठों पर डाली जाकर उस पर टिप्पणियां मांगी जाती हैं। आप लाख कोशिश करें, उस सामग्री को हटाया नहीं जाता, साधारण खाताधारी 7 से ज्यादा व्यक्तियों को एक दिन में दोस्त नहीं बना सकता, जबकि लोकप्रिय व्यक्तियों के खाते खुलते ही, घंटे दो घंटे में ही लाखों खाते जुड़ जाते हैं। यथार्थ में इसके पीछे पूरी जालसाजों की लॉबी काम करती हैं, इस पर लोकप्रियता का झूठा दिखावा करने के लिये करोड़ों रु. खर्च कर डाटा की खरीद बिक्री खुले में होती हैं, जबकि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी एक घंटे में ज्यादा से ज्यादा 100-200 जानकारी इकट्ठी कर उन्हें दोस्ती के लिये आमंत्रित कर सकता है। तो फिर लाखों प्रशंसक कहां से और कैसे जुड़ जाते हैं। वे सब धन और बल का कमाल होता है, फिर जानबूझकर विवादास्पद टिप्पणियों को उछालना, विवाद पैदाकर अपनी लोकप्रियता बढ़ाना न केवल फेसबुक, ट्वीटर और गूगल का व्यावसायिक पैंतरा हैं, कमाई का जितने विवादास्पद विचार उछलेंगे उतना ही लोग देखेंगे उतने ही विज्ञापन देखे जायेंगे उतनी ज्यादा कमाई होगी।

दूसरी ओर गूगल, फेसबुक, टवीटर आदि कं. को हर राष्ट्र की सरकारें इन्हें अपनी साख बचाये, बनाये रखने, सरकारों के विरुद्ध जनता के विचार जानने, उन्हें फैलने से रोकने और प्रतिबंधित करने के लिये अरबों रु. का धन चोरी छिपे बांटती ही है, साथ ही इनके पास संग्रहित समंकों का उपयोग जासूसी करने में भी करती ही हैं, जिसका सबसे बड़ा सच अमेरिकी जासूसी के बारे में अमेरिकी सरकारी एजेंसी के एक अधिकारी स्नोडेन ने कर ही दिया जो इस लेख की सत्यता को स्वयं प्रमाणित करता है।

पूरेविश्व में न केवल अमेरिका वरन अधिकांश अग्रिम पंक्ति के राष्ट्रों के लिये इन इलेक्ट्रानिक संचार माध्यमों तथा मोबाइल फोन्स इंटरनेट पर ईमेल और फेसबुक, ट्वीटर, गूगल, स्काइपे, लिंकोडिन जैसी सोशल साइटों ने न केवल अपने शत्रुओं वरन जनता की व्यक्तिगत जिंदगी की जासूसी करने में बड़ी आसान तकनीकें उपलब्ध करवा दी हैं। जहां एक इन सोशल साइटों को चलाने वाली कं. को आम शिक्षित जनता के रुझान पढ़ने, मस्तिष्कीय क्षमताओं को नापने और व्यक्तिगत व निजी जानकारी का न केवल भरपूर व्यावसायिक उपयोग वरन् सामरिक उपयोग भी करने की आड़ में ऐसी कं. को चौतरफा कमाई और दोहन के मार्ग भी प्रशस्त कर दिये हैं।

वास्तविकता में शिक्षित युवा वर्ग को इससे लाभ बहुत कम होता है, दूसरी ओर जीवन का महत्वपूर्ण समय के साथ कुछ समय के बाद अनावश्यक तनाव का कारण भी बनने लगती हैं, क्योंकि ये साइट्स आपके विचारों को आप जिनको पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंचे नहीं पर अनावश्यक ऐसे लोगों तक भी पहुंचा दी जाती हैं, जो इनका दुरुपयोग करते हैं। इस मामलों में लड़कियां, महिलायें ज्यादा उलझकर ज्यादा शिकार होती हैं। अधिकांश जालसाज अपनी जानकारियां झूठी डालकर महिलाओं को फंसाते हैं, उनके जज्बातों से खेलते हैं।

जब ये महिलायें पूरी तरह से चंगुल में फंस जाती हैं, तो खुलकर उनका आर्थिक, शारीरिक, मानसिक शोषण करते हैं। जिसमें ये सोशल साइट्स अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका दुःखद पहलू ये भी है, छोटी उम्र के युवा विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं। अपनी पढ़ाई की अपेक्षा इसमें समय ज्यादा व्यर्थ बर्बाद करने में जुटे रहते हैं। जिनकी जासूसी करवाने के लिये माता पिता को विवश होना पड़ता है।

## केन्द्र व राज्य सरकारों के हर विभाग में पदौन्नती हेतु परिक्षायें होनी चाहिए

# परीक्षाओं से प्रतिभाओं व योग्य कर्मियों से ही राष्ट्र की प्रगति संभव

**प्रतिभा और योग्यता को कुंठित कर राष्ट्र की बर्बादी मत करो।वोटों की राजनीति ने भ्रष्टाचार बढ़ाया व सरकारों को विफलता दी। 65 वर्ष बहुत हो गए...**

राष्ट्र की आजादी को 65 वर्ष हो गये। संविधान की जाति-धर्म की अपेक्षा हर नागरिक के समान अधिकार और समान अवसर की आत्मा को 65 वर्ष से कुचलने के अतिरिक्त हर पार्टी की सरकार ने वोटों की राजनीति के लिये जाति और धर्म के नामपर देश को बांटने के लिये क्या नहीं किया।

वोटों की राजनीति के लिये आरक्षण की भीख बांट कर जनता के अनुसूचित जाति, जनजातियों को पंगु बनाने के अतिरिक्त क्या किया। उन्हें आरक्षण देकर शासकीय विभागों में बैठाकर उन्हें अपनी तरीके जोत और हांककर इन राजनेताओं और उच्चाधिकारियों ने दोनों हाथ धन बटोरकर आंख भींच कर विदेशी बैंकों में जमा करते रहे।

अंग्रेजों ने तो हिन्दू-मुस्लिमों को लड़वाकर भारत में 300 वर्ष राज किया। इन्होंने उन हिन्दुओं में अगड़ा-पिछड़ा बनाकर जातिगत वैतनस्यता का बीज बोकर 50 वर्ष शासन कर लिया। इन षड्यंत्रों का जाल किसने बुना था, शायद भूल जाते हैं। वे ये भी भूल जाते हैं वे जो रु. 1 भेजते हैं उसका 40 पै. वे ही वापिस बटोरकर दूसरे हाथ से विदेशों में भेज देते हैं।

इसके षड्यंत्रों में शिक्षा, छात्रवृतियों से बढ़ते नौकरियों में आरक्षण फिर पदौन्नती में आरक्षण पहले 10 वर्ष फिर 10 वर्ष करते 65 वर्ष गुजर गये। हालात ये हो गये कि प्रतिभाओं और योग्यताओं ने राष्ट्र का भोजन, पानी, हवा का उपयोग कर शिक्षा ग्रहण की और विदेशों में जाकर बसने लग गये और अपनी प्रतिभाओं और योग्यताओं के दम पर अमेरिका, ब्रिटेन जैसे राष्ट्रों में बसकर उनकी सरकारों को चलाने और मार्गदर्शन देकर उन्हें विश्व के शीर्ष पर बैठाने में से मार्ग प्रशस्त कर दिया। आखिर क्यों इस राष्ट्र के राशन, पानी, हवा से तराशी प्रतिभायें विश्व के राष्ट्रों को अपने ज्ञान और प्रतिभाओं से न केवल प्रकाशित कर रही है, वरन उसी तकनीकी ज्ञान की भारत की जनता को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इसके दूसरी ओर जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी राष्ट्र में रहकर ही सेवा करने लगे तो वोटों की राजनीति ने न केवल उनका मूल वर्तमान और भविष्य बर्बाद कर दिया जिससे सबसे बड़ा नुकसान न केवल राष्ट्र और इसकी जनता के मूल और वर्तमान का हो रहा है वरन भविष्य को भी अंधकारमय बना दिया।

बेशक राष्ट्र निकम्में, जालसाज, भ्रष्ट, डकैत, मंत्रियों और इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर तहसीलों तक में बैठे इन जालसाज शूकरों को ज्ञानी, ध्यानी, प्रतिभाशाली, पीढ़ी नहीं चाहिये थी, क्योंकि उन हरामखोरों की लूट-खसोट पर भ्रष्टाचार पूर्ण कृत्यों पर वह अंगुली उठाती, इसलिये उन्हें तो चाहिये थे, जो इनके इशारों पर नाचे, जैसे चलाये वो चले और जैसा कहे वो करें। इसलिये मुख्य सचिव धूर्त भ्रष्ट निकम्मे ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को भी दरनिकार कर सामान्य वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों को 25-30 वर्षों से एक भी पदौन्नती नहीं देने दी और ऐसे-ऐसे नकारा निकम्मों को वरिष्ठ क्रम में पदौन्नतियां दे दी, जिन्हे डिग्री भी कृपांक से मिली हो और जो संचालक, सहा. संचालकों, उपसंचालकों से लेकर उपायुक्त, सहा. आयुक्त, मुख्य अभियंता, इंजीनियर इन चीफ मात्र वरिष्ठता के दम पर बना दिया गया। इन हरामखोर जालसाजों को काम से कोई मतलब नहीं, केवल कागजी खानापूर्तियां भी अपने स्टाफ के सामान्य वर्ग के होशियारों से करवाकर पूरे मप्र के सभी सरकारी विभागों में चला पा रह है। इस संबंध में समय माया ने पूर्व में ही लिखा था कि इन्हें आता-जाता काई खास नहीं, बस धन कैसे हड़पना है इस पर ही इन जालसाजों की निगाह रहती है और आपस में भ्रष्टाचार और लूट, कमीशनखोरी के संबंध में बतियाते है कि ब्राह्मण, बनियों ने खूब लूटा हमें अब हमारी बारी है तो हम भी लूट रहे हैं। अपनी कमाई से 10-20प्रतिशत सबको बांट दो कोई कुछ नहीं बोलता। सभी को टुकड़े डाल दो चाबते बैठेंगे तो बोलने का समय नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे। लोकायुक्त भी अगर केस बनायेगा तो उसको भी टुकड़े डालते रहोगे तो फाइल भी बाहर नहीं आयेगी। पदौन्नतीयां बैठे मिल ही जाती है। जो नियुक्ति के समय बीस-बीस वर्ष कनिष्ठ होते है पर 5-7 वर्षों में ही अपने वरिष्ठों के पीछे उनके ऊपर अधिकारी बन कर बैठ जाते है। फिर मोटा हजम करवाना, जिसके आने को उदाहरण अनेकों समाचार पत्रों में छपते रहते हैं। ऐसे अनेकों मामले समय माया ने भी प्रकाशित किये है। जिस में लोक स्वास्थ्य विभाग के मुख्य अभि. डामोर, के.के. सोनगारिया के प्रकाशित किये जा चुके है।

वरिष्ठता के आधार पर पदौन्नतियां देना राष्ट्र के लिये घोर घातक सिद्ध हो रहा है। एक तरफ जहां प्रतिभाशाली मेहनतकश अधिकारी कर्मचारियों सेवाओं का उचित तरह से राष्ट्रहित में दोहन नहीं किया जा रहा है। वहीं दूसरी और प्रतिभाओं और मेहनतकशों की कुंठित मानसिकता भ्रष्टाचार, कार्य के प्रति उदासिनता से राष्ट्र को दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। यह नुकसान केन्द्र व राज्य सरकारों के हर कार्यालय, मंत्रालयों से लेकर ग्रामीण स्तर की पंचायतों तक न्यायालयीन रक्षा सेनाओं, प्रशासनिक, राज्य प्रशासनिक सेवाओं, इंजिनियरों, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, शिक्षण संस्थाओं आदि सभी में हो रहा है, जबकि हर क्षेत्र में प्रतिभाये विद्यमान है, परंतु आरक्षण और वरिष्ठता के चलते, मेहनती, प्रतिभाशालियों को आगे आने के अवसर ही समाप्त कर दिये गये। मजबूरन अब पूरे राष्ट्र की पिछले 40 वर्षों से ज्यादा समय से वोटों की राजनीति के चलते हमारी प्रतिभाओं के पलायन से पूरे युरोपियन और खाड़ी देश उनका कम कीमत और वेतन पर भी भरपूर दोहन कर लाभांवित हो रहे है।

हामारा राष्ट्र युवाओं का राष्ट्र है। राष्ट्रोन्नति में उनका भरपूर उपयोग कर राष्ट्र को प्रगतिशील और श्रेष्ठ बनने और बनाने के लिये हमें हर क्षेत्र में मानव संसाधनों का उपयोग करने, उन्हें प्रोत्साहित करने, पदोन्नत करने के लिये परीक्षाओं के माध्यम से पूर्ण खोज परख करने के बाद वरिष्ठता के वार्षि अंक देकर 50प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण करने पर पदोन्नत किया जाना चाहिये।

पदोन्नतियां के लिसे हर दो वर्ष में लिपिक वर्ग से लेकर, उपर्यंत्रियों, सहा. यंत्रियों, नायब तहसीलदारों, तहसीलदारों, निरीक्षकोंस से वरिष्ठता कम में सिविल जजेस, सहा. अभियोजकों, चिकित्सकों, राज्य प्रशासनिक अधि. से भारतीय प्रशा. सेवाओं, पुलिस राजस्व, पांत्रिकीय विभागों, बैंकों, मंत्रालयों आदि में परीक्षायें लेकर ही पदोन्नत किया जाना चाहिये। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि सभी कर्मचारी अधिकारी कम से कम परीक्षा देने के लिये वास्तविक सैद्धांतिक कार्यशैली, कार्य पद्धति, नियम कानून के बारे में जान सकेंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण करने के बाद उस पद के दाखिलों, नियमों, कानूनों, कार्य पद्धतियों का उन्हें से अतिक ज्ञान तो होगा, दूसरी और प्रतिभाशाली और मेहनती कर्मचारी अधिकारी ही परीक्षायें उत्तीर्ण कर पदोन्नत हो पायेंगे ता जाति और वरिष्ठता न केवल निरर्थक हो जायेगी, इससे निकम्मे, भ्रष्ट, हरामखोर, कामचोर, बहानेबाज, आलसी, कर्मचारी और अधिकारियों को परीक्षाओं के कारण आसानी से बिना किसी लाभ लपेट न्यायालय के स्थगन आदेशों के ही पीछे ढकेला जा सकेगा।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9074551045, इंदौर कार्यालय- 0731-2530859, मोबा. 9300755803

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.